सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivahan_Vishesh

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 292, नई दिल्ली

रविवार, 31 दिसम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

ऊँचाई पर वही पहुँचते है,
जो बदला नहीं बदलाव
लाने की सोच रखते है।

नए साल पर ट्रैफिक पुलिस तैयार: कनॉट प्लेस-इंडिया गेट आने वाले हो जाएं सावधान, आठ बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री

दिल्ली पुलिस की नए साल के जश्न को लेकर कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर तैयारी पूरी है। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा यातायात नियम और हुड़दंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

संजय बाटला

नई दिल्ली। नए साल का जश्न मनाने वाले लोग रात 8 बजे तक ही कनॉट प्लेस के ईनर सर्किल में आ सकेंगे। भीड़ को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने रात आठ बजे के बाद कनॉट प्लेस में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैध पास और आपातकालीन वाहन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। नियम की अनदेखी करने वालों और हुड़दंगियों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।

लोगों की पहली पसंद पकनॉट प्लेस और इंडिया गेट

नए साल के आगमन का जश्न मनाने के लिए राजधानी के सभी इलाकों में व्यापक तैयारियां की जा रही है। नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों की पहली पसंद कनॉट प्लेस और इंडिया गेट है। कनॉट प्लेस के होटलों, पार्क और इंडिया गेट पर लोग काफी उत्साह से नए साल का आगमन करते हैं। हजारों की संख्या में लोगों के कनॉट प्लेस और इंडिया गेट आने की संभावना है। जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने यहां की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

रात आठ बजे के बाद नहीं होगी वाहनों की एंट्री

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार रात आठ बजे के बाद से नई दिल्ली इलाके के इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध जश्न के समापन तक जारी रहेगा। 8 बजे रात के बाद कनॉट प्लेस आने वाले निजी और सार्वजनिक वाहन मंडी हाउस, बंगाली मार्केट और गोल मार्केट क्षेत्र तक ही आ सकेंगे। कनॉट प्लेस के आंतरिक, मध्य या बाहरी सर्कल में केवल वैध पास वाले वाहनों को ही अनुमति होगी।

नियम तोड़ने और हुड़दंगियों पर दर्ज होगा मुकदमा

नए साल का जश्न मनाने के दौरान यातायात नियम तोड़ने, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हुड़दंग करने वाले पर मुकदमा दर्ज होगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि नियम तोड़ने और हुड़दंग करने वाले लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही इन इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी होगी। पुलिसकर्मियों को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली वासियों को नए साल की पूर्व संध्या को सुरक्षित और आनंदमय तरीके से मनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

इन जगहों पर वाहन पार्किंग कर सकेंगे

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को कनॉट प्लेस में अनुचित पार्किंग से बचने की सलाह दी है। कनॉट प्लेस के आंतरिक, मध्य या बाहरी सर्कल में वैध पास वालों को छोड़कर किसी भी वाहन चालक को पार्किंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यातायात पुलिस ने कनॉट प्लेस आने वाले वाहन चालकों को गोल डाक खाना के पास, काली बाड़ी मार्ग, पंडित पंत मार्ग और भाई वीर सिंह मार्ग पर वाहन पार्क करने की सलाह दी है।

नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

. नशे में गाड़ी चलाने
. तेज गति से गाड़ी चलाने
. स्टंट बाइकिंग
. लापरवाही से गाड़ी चलाने
. आड़ी तिरछी और खतरनाक ड्राइविंग

इंडिया गेट पर वाहनों पर प्रतिबंध

दिल्ली यातायात पुलिस ने भारी पैदल यात्री आवाजाही को देखते हुए वाहनों के सी-हेक्सागन इंडिया गेट क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वाहनों को इन जगहों से किया जाएगा परिवर्तित

क्यू प्वाइंट, आरएमएल, सुनहरी मस्जिद, जनपथ, कर्त्तव्य पथ, रफी मार्ग, विंडसर प्लेस, राजेंद्र प्रसाद रोड, केजी मार्ग, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस, डब्ल्यू प्वाइंट, मथुरा रोड, पुराना किला रोड, मथुरा रोड, शेरशाह रोड, जाकिर हुसैन मार्ग और पंडारा रोड

परिवहन विशेष
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र
Title Code : DELHIN28985
PARIVAHAN VISHESH NEWS

1. Web Portal https://www.newsparivahan.com/
2. facebook https://www.facebook.com/newsparivahan00
3. Twitter https://twitter.com/newsparivahan
4. Linkedin https://www.linkedin.com/in/news-parivahan-169680298/
5. Instagram https://www.instagram.com/news_parivahan/
6. Youtube https://www.youtube.com/@NewsParivahan

पर आप सभी के लिए 24 घण्टे उपलब्ध

3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, A-4 पश्चिम विहार, नई दिल्ली : 110063
सम्पर्क : 9212122095, 9811732095

www.newsparivahan.com, www.newstransport.in
Info@newsparivahan. com, news@newsparivahan.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

कोहरे का कहर: 200 उड़ानें और 60 से अधिक ट्रेनें प्रभावित, कम दृश्यता के चलते यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी

नई दिल्ली। राजधानी में शुक्रवार सुबह कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही। इससे हवाई और रेल सेवाएं सबसे अधिक प्रभावित हुईं। हवाई सेवाओं में 200 से अधिक विमानों को विलंब हुआ। इनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों सेवाएं शामिल हैं। कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। वहीं रेलवे की बात करें तो 60 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुईं। शुक्रवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण 200 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और कुछ को रद्द कर दिया गया। एयरलाइंस ने यात्रियों से एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले एयरलाइंस की वेबसाइट पर उड़ानों की स्थिति देखने का अनुरोध किया है। यूपी के रामपुर के रहने वाले फकरूल ने बताया कि उन्हें शारजाह की उड़ान पकड़ने के लिए ठंड में टी-3 पर 12 घंटे इंतजार करना पड़ा। ऐसे मौसम में देरी की स्थिति में एयरलाइन ने यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। हवाई अड्डे के सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार सुबह दृश्यता 150 मीटर रही, जो उड़ान संचालन के लिए मध्यम मानी जाती है। एक अन्य यात्री कुलदीप ने बताया कि उन्हें टोरंटो की उड़ान पकड़नी है, लेकिन उसमें देरी हो रही है।

19 घंटे की देरी से पहुंची वंदे भारत

कोहरे के कारण 56 ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं। इनमें प्रमुख रूप से बनारस-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 19.09 घंटे, कुरुक्षेत्र-खजुराहो गीता जयंती एक्सप्रेस 15.15 घंटे, मुंबई सेंट्रल-फिरोजपुर पंजाब मेल 12.10 घंटे, तिरुपति-हजरत निजामुद्दीन एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 14.15 घंटे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-नई दिल्ली ताज एक्सप्रेस 11.45 घंटे, रानी कमलापति-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 11.30 घंटे, चेन्नई-श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा अंडमान एक्सप्रेस 11.30 घंटे, पुणे-जम्मूतवी झेलम एक्सप्रेस 11.30 घंटे, लखनऊ-नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस 10.45 घंटे, पुरी-योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस-सवा दस घंटे, बरौनी-नई दिल्ली हमसफर क्लोन एक्सप्रेस-सवा नौ घंटे, रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस नौ घंटे, पुद्दुचेरी-नई दिल्ली एक्सप्रेस पौने नौ घंटे, रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस साढ़े आठ घंटे, खजुराहो-कुरुक्षेत्र गीता जयंती एक्सप्रेस साढ़े आठ घंटे, दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस आठ घंटे, बलरामपुर-ग्वालियर सुशासन एक्सप्रेस आठ घंटे, नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस सचखंड एक्सप्रेस सवा सात घंटे देरी से पहुंची।

राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने की सामूहिक अपील / तत्काल अपील

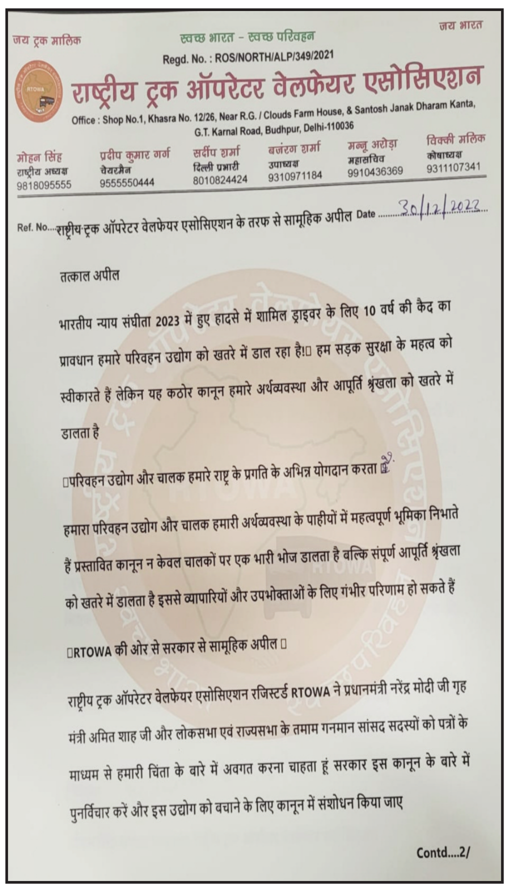

जय ट्रक मालिक — स्वच्छ भारत - स्वच्छ परिवहन — जय भारत
Regd. No. : ROS/NORTH/ALP/349/2021
राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन
Office : Shop No.1, Khasra No. 12/26, Near R.G. / Clouds Farm House, & Santosh Janak Dharam Kanta, G.T. Karnal Road, Budhpur, Delhi-110036

मोहन सिंह	प्रदीप कुमार गर्ग	सदीप शर्मा	बजरंग शर्मा	मन्नू अरोड़ा	विक्की मलिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष	चेयरमैन	दिल्ली प्रभारी	उपाध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष
9818095555	9555550444	8010824424	9310971184	9910436369	9311107341

Ref. No. राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से सामूहिक अपील Date 30/12/2022

तत्काल अपील

भारतीय न्याय संघीता 2023 में हुए हादसे में शामिल ड्राइवर के लिए 10 वर्ष की कैद का प्रावधान हमारे परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है! हम सड़क सुरक्षा के महत्व को स्वीकारते हैं लेकिन यह कठोर कानून हमारे अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालता है

परिवहन उद्योग और चालक हमारे राष्ट्र के प्रगति के अभिन्न योगदान करता है

हमारा परिवहन उद्योग और चालक हमारी अर्थव्यवस्था के पाहीयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रस्तावित कानून न केवल चालकों पर एक भारी भोज डालता है बल्कि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालता है इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं

RTOWA की ओर से सरकार से सामूहिक अपील

राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड RTOWA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह जी और लोकसभा एवं राज्यसभा के तमाम गनमान सांसद सदस्यों को पत्रों के माध्यम से हमारी चिंता के बारे में अवगत करना चाहता हूं सरकार इस कानून के बारे में पुनर्विचार करें और इस उद्योग को वचाने के लिए कानून में संशोधन किया जाए

Contd....2/

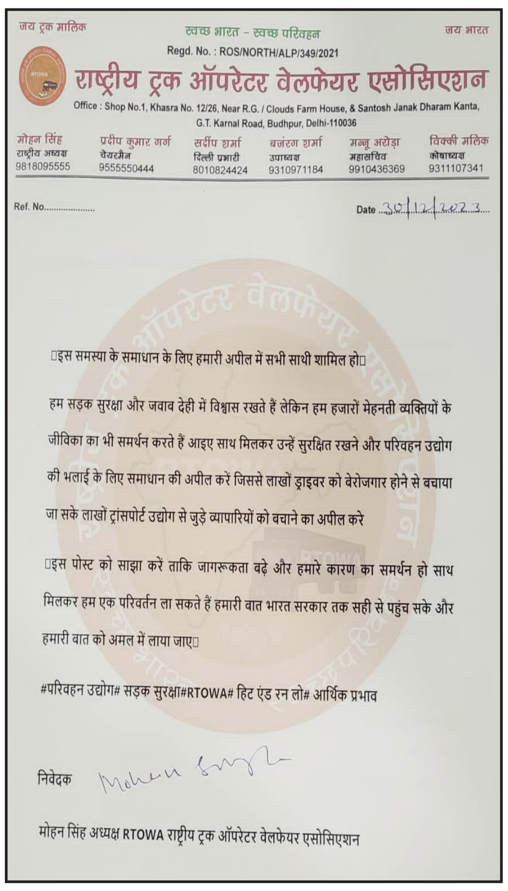

जय ट्रक मालिक — स्वच्छ भारत - स्वच्छ परिवहन — जय भारत
Regd. No. : ROS/NORTH/ALP/349/2021
राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन
Office : Shop No.1, Khasra No. 12/26, Near R.G. / Clouds Farm House, & Santosh Janak Dharam Kanta, G.T. Karnal Road, Budhpur, Delhi-110036

मोहन सिंह	प्रदीप कुमार गर्ग	सदीप शर्मा	बजरंग शर्मा	मन्नू अरोड़ा	विक्की मलिक
राष्ट्रीय अध्यक्ष	चेयरमैन	दिल्ली प्रभारी	उपाध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष
9818095555	9555550444	8010824424	9310971184	9910436369	9311107341

Ref. No.................... Date 30/12/2023

इस समस्या के समाधान के लिए हमारी अपील में सभी साथी शामिल हो

हम सड़क सुरक्षा और जवाब देही में विश्वास रखते हैं लेकिन हम हजारों मेहनती व्यक्तियों के जीविका का भी समर्थन करते हैं आइए साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित रखने और परिवहन उद्योग की भलाई के लिए समाधान की अपील करें जिससे लाखों ड्राइवर को बेरोजगार होने से बचाया जा सके लाखों ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े व्यापारियों को बचाने का अपील करे

इस पोस्ट को साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े और हमारे कारण का समर्थन हो साथ मिलकर हम एक परिवर्तन ला सकते हैं हमारी बात भारत सरकार तक सही से पहुंच सके और हमारी बात को अमल में लाया जाए

#परिवहन उद्योग# सड़क सुरक्षा#RTOWA# हिट एंड रन लो# आर्थिक प्रभाव

निवेदक Mohan Singh

मोहन सिंह अध्यक्ष RTOWA राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन

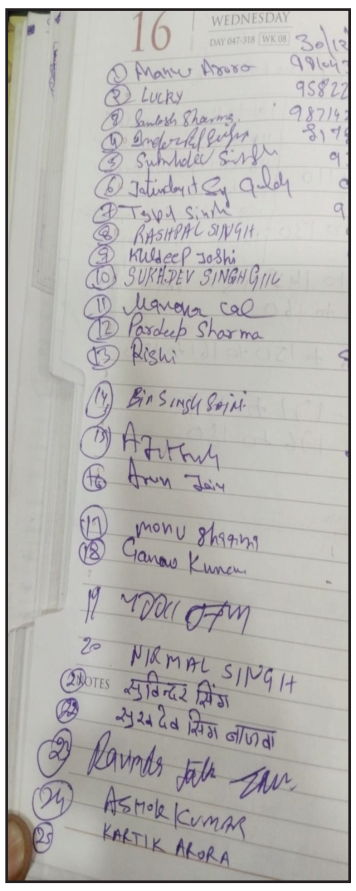

भारतीय न्याय संघीता 2023 में हादसे में शामिल ड्राइवर के लिए 10 वर्ष की कैद का प्रावधान
परिवहन उद्योग को खतरे में डाल रहा है! हम सड़क सुरक्षा के महत्व को स्वीकारते हैं लेकिन यह कठोर कानून हमारे अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालता है

परिवहन उद्योग और चालक हमारे राष्ट्र की प्रगति को अभिन्न योगदान करता

परिवहन उद्योग और चालक अर्थव्यवस्था के पहियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रस्तावित कानून न केवल चालकों पर एक भारी भोज डालता है बल्कि संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डालता है। इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा एवं राज्यसभा के तमाम गनमान्य सांसद सदस्यों को वाहन चालक की चिंता के साथ परिवहन क्षेत्र उद्योग को बचाने के लिए कानून में संशोधन पर पुन: विचार करना चाहिए।
हम सड़क सुरक्षा और जवाब देही में विश्वास रखते हैं लेकिन हम हजारों मेहनती व्यक्तियों के जीविका का भी समर्थन करते हैं आइए साथ मिलकर उन्हें सुरक्षित रखने और परिवहन उद्योग की भलाई के लिए समाधान की अपील करें जिससे लाखों ड्राइवरो को बेरोजगार होने से बचाया जा सके लाखों ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े व्यापारियों को बचाने की अपील करे

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

'ग्रामीण सेवा इको फ्रेंडली' करेगा विशाल धरना प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। विशाल प्रदर्शन ग्रामीण सेवा इको फ्रेंडली वालों की तरफ से तारीख 03.01 2024 दोपहर 2:00 बजे कालका मंदिर से डीसीपी ट्रेफिक साउथ वजह बार-बारहमारे लोगों ने पहले भी दो-तीन बार प्रदर्शन करने की कोशिश की तो ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ कभी एसीपी साहब कभी टीआई साहब आकर हमें आश्वासन देते हैं कि अब हम अपार्टमेंट से लेकर संगम विहार (गुरू रवि दास मार्ग)के बीच में नो एंट्री ई रिक्शा को नहीं चलने देंगे गोविंदपुरी मेट्रो से लाल कुआं (मां आनन्द मई मार्ग)तक शेयरिंग ऑटो नही चलने देगे सिर्फ आश्वासन देने के बाद सभी ऑफिसर अपनी बात से मुकर जाते हैं और कुछ सीनियर ऑफिसर ने ताकि उन तक वीडियो या फोटो ना पहुंचे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया जबकि गुरु रविदास मार्ग पर एलजी साहब के द्वारा ई रिक्शा पर पूरी तरीके से रोक है उसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस स्टाफ उन्हें खुलेआम अपने सामने चलने दे रहा है धरने में कम से कम ४०० ग्रामीण सेवा एको फ्रैंडली सेवा आरटीवी मिनी बस सामिल होगी

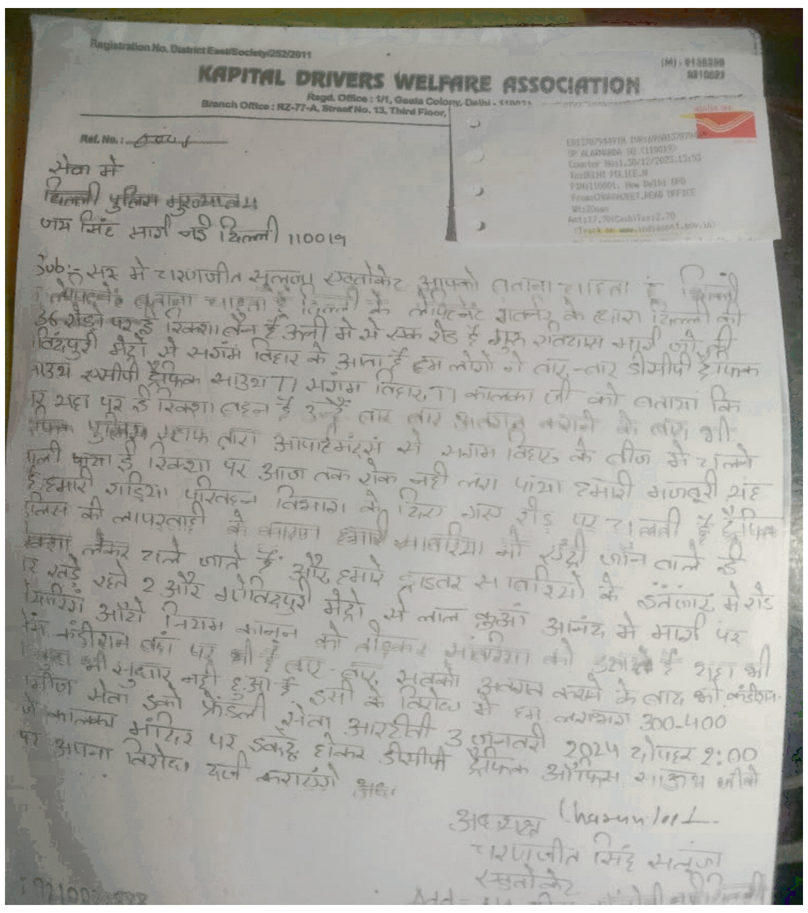

KAPITAL DRIVERS WELFARE ASSOCIATION

इनसाइड

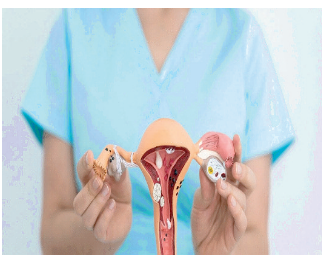

फीमेल ऑर्गेज्म से जुड़े हैं ये 5 अज्ञात फैक्ट्स, जानकर आप भी हो जाएंगी हैरान

महिलाओं के शरीर से जुड़े फैक्ट्स महिलाओं को खुद पता नहीं होते हैं. उन्हें अपने शरीर के बारे में समझने की जरूरत है, खुलकर बात करने की जरूरत है, न की इस पर चुप रहने की. सेक्स जरूरी है और इससे जुड़े अंग जो आपको उत्तेजित करते हैं उसके बारे में जानना भी जरूरी है. आज हम 5 ऐसे ही अज्ञात तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपको हैरानी होने वाली है'

महिलाओं में 3 से अधिक यौन अंग होते हैं! महिला के बाहरी यौन अंग को लेबिया मेजोरा कहा जाता है. यह योनि के खुलने के आसपास वाली त्वचा होती है, जो 2 फोल्ड्स में मौजूद होती है. भीतरी यौन अंग को लेबिया माइनोरा कहा जाता है, जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होते हैं. आंतरिक महिला यौन अंग में अंडाशय (Ovaries), फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय (Uterus), गर्भाशय ग्रीवा (Cervix) और योनि (Vagina) हैं. महिला सेक्स सिर्फ प्रजनन (Reproductive) अंग नहीं हैं, वे महिलाओं में यौन उत्तेजना का भी काम करते हैं.

विभिन्न चरणों में समझे फीमेल ऑर्गेज्म जिस तरह से एक महिला को ऑर्गेज्म प्राप्त होता है वह पुरुषों की तुलना में अलग होता है. पहले एक उत्तेजना चरण होता है जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से प्रेरित होता है. दूसरा जब क्लाइटोरिस प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है. क्लाइटोरिस को "फीमेल पेनिस" भी कहते हैं, जो महिलाओं के शरीर का सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला अंग माना गया है. तीसरा चरण ऑर्गेज्म से ठीक पहले होता है जहां हृदय गति सबसे अधिक होती है. अंतिम चरण रिलीज या संभोग का चरण है.

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग

क्लाइटोरिस सबसे अधिक उत्तेजित करने वाला अंग इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें 8,000 से अधिक तंत्रिका हैं. इस प्रकार से यह सबसे अधिक उत्तेजना उत्प्रेरण अंगों में से एक है. ऐसा कहा जाता है कि 75 प्रतिशत से अधिक महिलाओं में क्लाइटोरिस को छूने पर ही ऑर्गेज्म चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है. तीन-चौथाई क्लाइटोरिस छिपे हुए होते हैं शायद इसीलिए इसे कामोत्तेजना वाले अंग के रूप में नहीं देखा जा सकता है. क्लाइटोरिस का एकमात्र उद्देश्य महिलाओं को आनंद देना होता है.

फीमेल ऑर्गेज्म में स्तन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

महिलाओं में स्तन और निप्पल की उत्तेजना के कारण भी ऑर्गेज्म प्राप्त किया जा सकता है. अध्ययनों से पता चला है कि निप्पल को उत्तेजित करने से भी जेनाइटल्स यानी जननांगों को सक्रिय किया जा सकता है.

महिला को आनंद देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं

महिलाओं को सुख देने वाले अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक अंग से प्रत्येक अंग उत्तेजित होता है. जिस वजह से महिलाओं को अधिक आनंद की प्राप्ति होती है. पार्टनर की प्राथमिकता, पसंद और सेक्सुअल एनाटॉमी को ध्यान में रखें. इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान यह महत्वपूर्ण होता है.

महिलाओं में होने वाली हेल्थ से जुड़ी परेशानियां, जिनके बारे में जानना है बेहद जरूरी

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कुछ अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की संभावना अधिक रहती है लेकिन समय पर इलाज होने पर उपचार संभव है. जानिए महिलाओं में होने वाली कुछ सामान्य हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के बारे में. क्या आप जानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हार्ट अटैक डेथ्स की संभावना अधिक होती हैं. यही नहीं, डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या भी महिलाओं में अधिक देखी जाती है. महिलाओं और पुरुषों दोनों कई हेल्थ कंडिशंस से गुजरते हैं लेकिन कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, जो महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं. वहीं जानकारी की कमी या लापरवाही के कारण कई महिलाओं की हेल्थ कंडिशंस का समय पर निदान नहीं हो पाता.

छात्राओं का बढ़ता यौन उत्पीड़न रोकें

छात्राओं का यौन उत्पीड़न शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें। क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी व कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए'

डा. वरिंदर भाटिया

देश के अनेक राज्यों के शिक्षा संस्थानों मे छात्राओं का यौन शोषण चिंताजनक बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हाल ही में कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीडऩ की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीडऩ की रोकथाम के लिए प्रभावी क़दम उठाने के निर्देश दिए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीडऩ की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इसके तहत दिए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से अमल सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें। आयोग ने कहा है कि हाल के सालों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ दुनिया भर में महिलाओं को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है। आयोग कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीडऩ की घटनाओं को लेकर चिंतित है। आयोग ने सभी हितधारकों के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए भी कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम की जगह पर यौन उत्पीडऩ के मामले जिम्मेदारी और प्रभावी ढंग से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा है कि ये कोचिंग सेंटर संबंधित प्राधिकरण में पंजीकृत हों और केंद्रों को चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की गई हो। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) विधेयक 2012 (संशोधित विधेयक) संसद द्वारा 2013 में पारित किया गया था। यौन उत्पीडऩ कानून संगठित और असंगठित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। हमारी जानकारी के लिए, किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी लालच देकर अनावश्यक रूप से दबाव बनाना भी यौन शोषण अपराध का हिस्सा होता है। कार्यस्थल पर अश्लील चित्र दिखाना, शरीर के यौन अंग पर टिप्पणी करना, यौन गतिविधियों की अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी महिला के साथ अभद्रता या गाली गलौज करना भी यौन शोषण के अंतर्गत आता है। शिक्षा के मंदिर इसका अपवाद नहीं हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं की तुरंत रिपोर्टिंग की जरूरत होती है परन्तु छात्राओं द्वारा किन्हीं कारणों से इसको न बताने पर उनका शोषण बढ़ता जाता है। बेहतर है सरकारें छात्राओं से मिली इस जानकारी को गुप्त रख छद्म जांच करें और कार्रवाई करें। कुछ समय से देश के अनेक राज्यों में छात्राओं के यौन शोषण की घटनाओं में बढ़ोतरी से सामाजिक व्याकुलता बढ़ रही है। यौन शोषण का छात्राओं के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जिस मनुष्य का यौन शोषण हुआ होता है वह पूरी मानवता से नफरत करने लगता है। उसे हर व्यक्ति केवल शोषण करने वाला ही दिखता है क्योंकि यह उसकी मानसिकता बन जाती है जिसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है और उसके लिए बहुत सी तकलीफों का सामना भी करना होता है, जैसे कि वह यौन शोषण उसे बार-बार याद आते रहते हैं और उसको और ज्यादा मानसिक तकलीफ होती है जो उसके लिए बहुत कष्टदायक होती है, यह जिस तन लागे वोही जाने वाली स्थिति होती है। आज सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्राओं के यौन उत्पीडऩ की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कुछ समय पहले एक छात्र ऑडिट के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय के 24 कॉलेजों और विभागों में सर्वेक्षण किया गया। कुल 810 छात्र-छात्राओं ने सवालों के जवाब दिए। इसमें करीब 90 प्रतिशत महिलाएं और 10 प्रतिशत पुरुष थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हर चार छात्राओं में से एक ने यौन उत्पीडऩ की शिकायत की। यौन उत्पीडऩ के 188 मामलों में 40 मामले शारीरिक उत्पीडऩ के थे। उत्पीडऩ के पांच में से एक मामला जबरदस्ती छूने या पकडऩे का था। उत्पीडऩ के प्रत्येक पांच मामलों में से एक सोशल मीडिया पर ट्रोल करने या कॉल या लिखित वॉट्सऐप मैसेजों के जरिए उत्पीडऩ का था।

जवाब देने वाले तकरीबन 80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने परिसर में असुरक्षा के लिए विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन की ओर से कदम नहीं उठाने को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा ऑडिट सरकारों की तरफ से सभी कॉलेजों में करवाया जाना चाहिए। सच बोलें तो सिर्फ छात्राएं ही नहीं, अमूमन सभी लड़कियों की लाइफ बहुत टफ होती है। उन्हें हर कदम पर न जाने कितनी गंदी नजऱों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर उन्हें खुद को सुरक्षित रखने की चिंता लगी रहती है। ऑफिस या स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, अब तो लड़कियां घर तक पर सेफ नहीं हैं। आए दिन पिता या भाई द्वारा भी रेप की खबरों से सोशल मीडिया भरा रहता है। ऐसे माहौल में आप भी समझ सकते हैं कि यौन उत्पीडऩ की वजह से लड़कियों के लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी लड़कियों को यहां तक कि तदर्थ महिला अध्यापकों को भी पक्की जॉब के लिए यौन उत्पीडऩ का शिकार होना पड़ता है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल रहते हैं जो बेडरूम सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। यह एक न हजम होने वाली सच्चाई हो सकती है। छात्राओं के यौन शोषण को लेकर विदेश की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आता है लेकिन पिछले कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहां पर छात्राओं का यौन उत्पीडऩ सबसे ज्यादा होता है। कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों का यौन उत्पीडऩ किया जाना ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में महामारी के स्तर तक पहुंच चुका है। वहां की कई यूनिवर्सिटियों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कर्मचारियों को विद्यार्थियों पर यौन संबंध के लिए दबाव बनाने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, ऐसा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी पर्याप्त नियम नहीं हैं। बस इसी बात से आप जान सकते हैं कि जब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में लड़कियों और स्टूडेंट्स का ये हाल है तो फिर बाकी कॉलेजों में स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा होगा। एक ज़माने में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को विद्या का मंदिर समझा जाता था और आज अपने देश में भी इनमें से कुछ की छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो गई है कि अब इन्हें विद्या का मंदिर नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकारें ऐसे इंतजाम करें, ऐसे रिपोर्टिंग सिस्टम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कहें जिससे छात्राओं के यौन शोषण के मामले दबे नहीं।

छात्राओं का यौन उत्पीडऩ शिक्षा समाज में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। इसे राज्य सरकारें कभी भी हल्के से न लें, क्यों न हमारे पत्रकार दोस्तों और सरकारों द्वारा यह पड़ताल की जाए कि राज्यों के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स में छात्राओं की अस्मत की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। कहीं पर छात्राओं के यौन उत्पीडऩ की घटना होने पर शिक्षा संस्थानों पर तुरंत वाजिब एक्शन लोकहित में होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि छात्राओं की पढ़ाई-लिखाई को उत्साह देने के लिए उन्हें सुरक्षित अकादमिक माहौल दिया जा सके। छात्राओं के हॉस्टल उनके लिए कितने सुरक्षित हैं, यह वैरिफिकेशन जरूरी और तुरंत हो तो बेहतर है। छात्राओं को सुरक्षित करना ही होगा।

मां बनने के बाद छोटी-छोटी बातें भूलने लगी हैं, तो 'मॉमी ब्रेन' प्रॉब्लम से ऐसे करें बचाव

क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मां बनने के बाद छोटी छोटी बातें भूलने लगीं हैं? कभी ऐसा हुआ हो कि आप कमरे में तेजी से गईं और वहां जाकर भूल गईं कि आप क्यों कमरे में आईं या गाड़ी की चाबी हाथ में हैं और आप पूरे फ्लैट में चाबी ढूंढती रहीं? अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हो गई हैं तो यह अकेले आपकी ऐसी समस्या नहीं है. दरअसल इस समस्या को मॉमी ब्रेन के नाम से जाना जाता है. वेरीवेलफैमिली के मुताबिक एक स्टडी में पाया गया है कि बच्चे को जन्म देने से मां का मस्तिष्क भी काफी प्रभावित होता है और कभी-कभी लंबे समय तक इसका असर कायम रहता है. ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने भी ये पाया गया है कि मां बनने से महिला के याददाश्त क्षमता पर स्थाई असर पड़ता है.

क्या है इस परेशानी की वजह?

कई शोधकर्ताओं ने माना कि ये परिवर्तन एक नई मां को अपने बच्चे की देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाने का एक नेचुरल तरीका होता है. यह भी कहा जा सकता है कि मस्तिष्क में ये परिवर्तन दरअसल नई माताओं को बच्चे की ज़रूरतों को अपनाने और उन्हें पूरा करने के लिए अहम होता है.

मॉमी ब्रेन से उबरने के उपाय

धैर्य रखें- शरीर में हुए इस बायोलॉजिकल बदलाव की वजह से आप खुद से परेशान हैं और इरिटेट हो जाती हैं आपको बता दें कि अगर आप थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी काम को पूरा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्लान बनाएं तो मॉमी ब्रेन की समस्या से उबर सकती हैं.

लिस्ट बनाएं- इस समस्या से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप अपने हर काम की लिस्ट बनाएं. इसके लिए आप एक नोटबुक कैरी करें और जब भी कुछ याद आए तो उसे लिख लें. ऐसा करने से आप जरूरी चीजों को भूलेंगी नहीं.

प्लान बनाएं- आप पहले से चीजों के लिए प्लान बनाएं और अपनी हर चीज को सही जगह पर रखने की आदत डाल लें. इससे आपका काम काफी आसान बन जाएगा. मसलन, आप अगर सुबह डॉक्टर के पास जाने वाली हैं तो रात में ही सारा सामान तैयार रखें. आप चाभी, वॉलेट आदि हमेशा एक ही जगह पर रखें आदि.

पर्याप्त नींद जरूरी- नई मांओं की व्यस्तता 24 घंटे की होती है. लेकिन आपको कुछ इस तरह अपने रुटीन को फॉलो करना है कि आपकी नींद पूरी हो सके. इसके लिए आप परिवार के लोगों की मदद ले सकती हैं और बच्चे के साथ ही सोने और जागने की रुटीन को फॉलो कर सकती हैं. भरपूर नींद आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर पाएगा.

ब्रेन को दें एक्स्ट्रा केयर- ब्रेन के लिए आप अपने खानपान पर ध्यान दें और ब्रेन गेम खेलें. ब्रेन गेम आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करेगा और ये बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. इसके अलावा, आप उन चीजों को डाइट में शामिल करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो और भरपूर प्रोटीन हो.

ज्यादा वजन भी बन सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह, इन तरीकों से करें बचाव

हाई रिस्क प्रेगनेंसी के खतरे से खुद को बचाना है तो समय-समय पर अपनी जांच जरूर कराती रहें. इसके अलावा, जहां तक हो सके प्रेगनेंसी में तनाव से दूर रहें, भरपूर आराम करें और रोजाना योग जरूर करें. इन बातों का ध्यान रखकर आप इस खतरे से बच सकती हैं.

मां बनने का सपना हर महिला देखती है. लेकिन कई महिलाओं में सेहत से जुड़ी समस्याओं की वजह से उनकी प्रेगनेंसी कठिनायों से भरी होती है. कई बार तो उनके लिए प्रेगनेंसी जोखिम भरा हो जाता है और इससे मां और पेट में पल रहे बच्चे की जान तक जा सकती है. इसी जोखिम को 'हाई रिस्क प्रेगनेंसी' कहा जाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में तकरीबन 5,29,000 महिलाओं की मौत गर्भावस्था के दौरान इन खतरों की वजह से हो जाती है. इसकी वजह खराब सेहत, बदलती लाइफस्टाइल, खान पान में लापरवाही को माना जाता है. यही नहीं, कई बार ऐसी समस्याएं किसी बीमारी या जेनेटिक डिजीज की वजह से भी हो सकती है.

हाई रिस्क प्रेगनेंसी की ये हैं बड़ी वजह

एनआईएच के मुताबिक अगर महिला को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है या वो एचआईवी पॉजिटिव है तो उसे प्रेगनेंसी में रिस्क की समस्या हो सकती है. अगर महिला का वजन ज्यादा है तो इससे हाई ब्लड प्रेशर, प्रीक्लेम्पसिया, गर्भकालीन मधुमेह, स्टिलबर्थ, न्यूरल ट्यूब दोष और सिजेरियन डिलीवरी की समस्या हो सकती है. इसकी वजह से जन्म के समय नवजात में हृदय रोग का खतरा 15% तक बढ़ सकता है.

किशोरावस्था और 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में गर्भावस्था की वजह से प्रीक्लेम्पसिया और गर्भकालीन उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह बन सकता है. गर्भाशय में हुई कोई पुरानी सर्जरी की वजह से भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है. इसके अलावा, जुड़वा बच्चों और आईवीएफ द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया भी महिलाओं में रिस्की प्रेगनेंसी की वजह हो सकता है.

हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचाव का तरीका

अगर आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी से बचना चाहती हैं तो समय-समय पर अपनी जांच कराती रहें. इसके अलावा, प्रेगनेंसी में तनाव से बचें, भरपूर आराम करें, रोजाना योग ध्यान करें, फ्रेश हवा में वॉक पर जाएं, हेल्दी खान पान करें और डॉक्टर की संपर्क में रहें.

कार में शराब पीने पर होगी जेल,नशे में हुडदंग पर 5000 जुर्माना

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नया साल 2024 दस्तक देने वाला है। जश्न की तैयारियां शबाब पर है ।लेकिन ठहराये कहीं नए साल के जश्न में खलल में पड जाए। अक्सर देखा गया है कि कार को बार की तरह इस्तेमाल कर हार्ड ड्रिंक्स लेने कक खामियाजा भी भुगतना पड सकता है। कार में शराब पीने पर हो सकती है जेल। और अगर शराब के नशे में पब्लिक प्लेस में हुडदंग मचाने पर 5000 रूपये जुर्माना भुगतने को भी तैयार रहे। दिल्ली पुलिस इस तरह की किसी भी गैर कानूनी तरीके को अपनाने पर सख्ती के मूड में है। बहरहाल घर पर गेस्ट एंजोयमेंट के कानूनी तरीके में हार्ड ड्रिंक्स परोसने का एक्साइज के नियमों के मुताबिक

अस्थाई लाइसेंस लेना जरूरी है। बता दें कि 9 लीटर से ज्यादा हार्ड लिकर सर्व करने पर लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर इससे ज्यादा शराब परोसी जाती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट जुर्माने साथ लेकर जब्त कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मोटे, बैंक्विट हॉल, फार्म हाउस, में पी-10 लाइसेंस के लिए 15000 रूपये फीस है ।जबकि दूसरी जगहों के लिए 5000 रूपये लगते हैं ।प्राईवेट पार्टी , होटल और रेस्तरां में इवेंट के लिए 10000 रूपये खर्च लगता है।

लिहाजा पब्लिक प्लेस में कोई भी शराब नहीं पी सकता। इसे लेकर राज्यों में अलग-अलग नियम-कानून है ।सडक, पार्क, दुकान जैसी जगहों पर शराब पीने ,हुडदंग मचाने पर कडे नियम हैं।

विपश्यना ध्यान केंद्र से वापस लौटे सीएम केजरीवाल, बोले- इस साधना से मिलती है असीम शांति

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 10 दिन की विपश्यना साधना बाद वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि अब नई ऊर्जा के साथ फिर जनता की सेवा में लगेंगे।

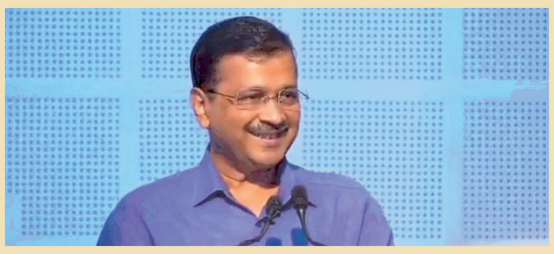

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को विपश्यना ध्यान केंद्र से निकले हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, '10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे।' 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापिस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को समन भेजा था। इस दौरान सीएम केजरीवाल पहले से तय विपश्यना कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए थे। वह विपश्यना ध्यान केंद्र में 30 दिसंबर तक मौजूद रहे। विपश्यना एक प्राचीन भारतीय ध्यान पद्धति है, जिसका अभ्यास करने वाले लोग कुछ समय के लिए देश-दुनिया से कट जाते हैं और एकांतवास में रहते हैं। इसे एक तरह का योगाभ्यास भी कहा जा सकता है।

सात साल बाद सबसे गर्म रहा दिसंबर, अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री रहा; दिल्ली में येलो अलर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आंशिक रूप से आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। 2023 में दिसंबर का औसत तापमान 24.2 डिग्री रहा है।

मौसमी दशाओं में आए बदलाव के कारण सात साल बाद इस बार दिसंबर सबसे गर्म दर्ज किया गया। इस दौरान औसत अधिकतम तापमान करीब 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले साल 2016 में 24.5 डिग्री रहा था। इस साल 30 दिसंबर तक एक भी शीत लहर या शीत दिवस दर्ज नहीं हुआ।

साल 2017 में भी पूरे माह एक भी दिन शीतलहर या शीत दिवस दर्ज नहीं हुआ था, जबकि बीते सालों में शीत दिवस या शीतलहर में से एक या दोनों दर्ज हुए थे। इस साल दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ भी कमजोर रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान की बात करें तो छह साल बाद साल 2023 के दिसंबर में औसत न्यूनतम तापमान करीब 8.47 डिग्री रहा।

इससे पहले साल 2017 में औसत न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो मौसमी दशाओं में आए बदलाव के कारण दिसंबर गर्म रहा। मौसम में आए इस बदलाव के पीछे कारणों को जानने व जलवायु परिवर्तन का पता लगाने के लिए बढ़े स्तर पर अध्ययन की जरूरत है। इसके बाद ही सटीक कारण स्पष्ट हो पाएगा।

सुबह का तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक

प्रादेशिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री रहा जबकि न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे के कारण सफदरजंग केंद्र पर सुबह साढ़े आठ बजे 200 मीटर की दृश्यता रही। रिज क्षेत्र में यह 500 मीटर के करीब रही।

मौसम विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 19 डिग्री व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रह सकता है। सोमवार तक तक पारा गिरेगा, इसके बाद तापमान में बढ़त की उम्मीद है।

नरेला रहा सबसे ठंडा

शनिवार को दिल्ली का नरेला सबसे अधिक ठंडा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि लोधी रोड और रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान सबसे कम 11 डिग्री दर्ज किया गया।

रेलवे में फर्जी मेडिकल बिल के नाम पर 15 लाख रुपये से ज्यादा का फर्जीवाड़ा, एएसओ सस्पेंड

रेलवे के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रेलवे में 15 लाख रुपये से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ है।

दिल्ली रेलवे में फर्जी मेडिकल बिल के नाम पर 15 लाख रुपये से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस मामले में रेलवे के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (एएसओ) को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में नई दिल्ली जिले के साइबर सेल थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में चार बैंक खाते में घोटाले की रकम भेजी गई है। फिलहाल इसे सीज कर दिया गया है।

भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने शनिवार को अपना पुरस्कार लौटाया

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार दिन पहले अपने अर्जुन अवॉर्ड को लौटाने का ऐलान कर चुकीं भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने शनिवार को अपना पुरस्कार लौटा दिया। विनेश ने अपने पति सोमवीर राठी के साथ अपना अवॉर्ड कर्तव्य पथ पर रख दिया। इस दौरान विनेश फोगाट ने पीएम आवास की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका जिसके बाद उन्होंने अपना सम्मान वहीं सड़क पर ही रख दिया।

वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तीन आरोपी रिहा, कोर्ट ने हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को दी स्वीकृति

नई दिल्ली। चाइनीज स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो इंडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी होंग ज़ुक्वान, हरिंदर दहिया और हेमंत मुंजाल को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। शनिवार को मामले की सुनवाई दिल्ली की पटियाला कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली आरोपियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकृति दे दी।

मधुमेह रोगियों में हो सकते हैं मानसिक विकार, 42 करोड़ से ज्यादा लोग हैं ग्रस्त; भारत में सबसे ज्यादा

दुनिया भर में करीब 42 करोड़ से ज्यादा लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है, इस वजह से इसे दुनिया की मधुमेह राजधानी कहते हैं। मधुमेह की चपेट में आने वाले रोगियों में सामान्य मानसिक विकार भी हो सकते हैं।

मधुमेह की चपेट में आने वाले रोगियों में सामान्य मानसिक विकार भी हो सकते हैं। यह जानकारी नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक अध्ययन में सामने आई है, जिसमें डॉक्टरों ने मधुमेह रोगियों में मानसिक विकारों के पुख्ता सबूत खोजे हैं।

डॉक्टरों का मानना है कि समय पर जांच न होने की वजह से मानसिक विकारों के बारे में पता नहीं चल पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मधुमेह रोगियों को इन विकारों का जोखिम नहीं है। दिल्ली एम्स के सामुदायिक चिकित्सा विभाग, मनोरोग और हृदय जैव रसायन विभाग के डॉक्टरों ने तेलंगाना के बीबी नगर स्थित एम्स के साथ मिलकर 211 मधुमेह और 273 गैर मधुमेह रोगियों पर अध्ययन किया, जिसे इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित किया है।

अध्ययन हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ क्षेत्र के 28 गांवों के उन लोगों पर किया गया, जिन्हें कम से कम एक साल से मधुमेह की शिकायत है। अध्ययन में मधुमेह, अवसाद व चिंता सभी तथ्यों को लेकर जांच की गई। इसके बाद 173 मधुमेह रोगी और 175 गैर मधुमेह रोगियों पर अध्ययन शुरू हुआ। निष्कर्ष बताते हैं कि 67.5% मधुमेह रोगियों में अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य परेशानियों की पुष्टि हुई है, जबकि गैर मधुमेह वाले लोगों में से 37.5% में यह परेशानी दर्ज की गई।

डॉक्टरों का कहना है, यह अध्ययन 10 में से लगभग सात मधुमेह रोगियों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों की आशंका जता रहे हैं, जो बड़ा आंकड़ा है। डॉक्टरों ने यह भी अनुमान जताया कि दुनिया भर में सामान्य आबादी की तुलना में मधुमेह एक और दो से ग्रस्त रोगियों में अवसाद के मामले क्रमशः दो से तीन गुना ज्यादा हो सकते हैं।

दिल्ली एम्स के वरिष्ठ डॉ. हर्षल रमेश साल्वे ने बताया, दुनिया भर में करीब 42 करोड़ से ज्यादा लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा है, इस वजह से इसे दुनिया की मधुमेह राजधानी कहते हैं। देश के महानगरों में हुए राष्ट्रीय शहरी मधुमेह सर्वे के अनुसार, भारत में 20 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क में 12.1% मधुमेह ग्रस्त हैं। हाल में आईसीएमआर-इंडियाबी का भी एक अध्ययन सामने आया है, जिसमें 20 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में से 13.6% तक मधुमेह ग्रस्त हैं।

अध्ययन में डॉक्टरों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि देश में अभी मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग कार्यक्रम एनसीडी के साथ अवसाद यानी सामान्य मानसिक विकारों के बारे में भी काम करने की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है, सामान्य मानसिक विकारों और मधुमेह का एक साथ प्रबंधन करना समय की मांग है।

कार में लगी आग, बाल-बाल बचा चालक...

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के हरि नगर इलाके में शुक्रवार रात चलती आई 20 कार में अचानक आग लग गई। इंजन से धुआं निकलता देख चालक ने कार से बाहर निकलकर जान बचाई और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। आग की तेज लपटें निकलते देख उसने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी।

मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने एक गाड़ी की मदद से कुछ देर में आग पर काबू पा लिया। तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। पुलिस कार को जब्त कर आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात 8.55 बजे पुलिस और दमकल विभाग को हरिनगर की डीटीसी कालोनी के पास एक कार में आग लगने की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही हरिनगर फायर स्टेशन से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। आई 20 कार से आग की लपटें निकल रहीं थीं। दमकल कर्मियों ने कुछ देर में आग पर काबू पा लिया। कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी।

कार चला रहे चालक की पहचान बी ब्लॉक हरिनगर निवासी विक्रम के रूप में हुई। विक्रम ने बताया कि घटना के समय अपनी कार से घर की ओर जा रहे थे। अचानक कार के अगले हिस्से से धुआं निकलने के बाद आग लग गई। विक्रम ने खुद कार से निकलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। फिर उन्होंने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की वजह से आग लगने की बात सामने आई है। कार की तकनीकी जांच करवाकर पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है।

सुनहरी बाग मस्जिद: इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, कहा- सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है मस्जिद

सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि यह एक विरासती इमारत है, जो सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

सुनहरी बाग मस्जिद के इमाम ने क्षेत्र में कथित यातायात भीड़ के कारण संरचना के प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता अब्दुल अजीज ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा 24 दिसंबर को जारी एक सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी है। इसमें मस्जिद के विध्वंस के संबंध में एक जनवरी तक आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

न्यायमूर्ति मनोज जैन की अवकाश पीठ ने एनडीएमसी के वकील के आश्वासन के बाद याचिका को आठ जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। इस बीच कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कार्रवाई पर अंतिम फैसला विरासत संरक्षण समिति (एचसीसी) को करना है। एनडीएमसी के वकील ने कहा, 'आपका आधिपत्य इसे बस स्थगित कर सकता है। कुछ नहीं होने वाला है। निर्णय एचसीसी को लेना है, हमें नहीं। हमें सिर्फ सुझाव मांगने हैं।' उन्होंने कहा, 'मैं एचसीसी की अनुमति के बिना एक ईंट भी नहीं छू सकता।'

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वह इस स्तर पर अंतरिम आदेश के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं और तर्क दिया कि कानून एनडीएमसी को एक विरासत संरचना को हटाने की शक्ति नहीं देता है। उन्होंने कहा, 'अदालत याचिका को रोस्टर बेंच के समक्ष सूचीबद्ध कर सकती है। उन्हें निर्देश लेने दीजिए। मैं कोई स्थगन आदेश नहीं मांग रहा हूं।' अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के बजाय इमाम के याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया।

इमाम के वकील ने कहा कि उन्होंने अपनी मंडली की रक्षा के लिए याचिका दायर की है, क्योंकि सुनहरी बाग मस्जिद एक कामकाजी मस्जिद है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि मस्जिद 150 साल से अधिक पुरानी है और एक विरासत इमारत है, जो सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू, नए साल के जश्न की आड़ में नहीं कर सकेंगे हुड़दंग

नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अनुसार किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जा सकेगी।

नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने नए साल के दौरान होने वाले हुड़दंग को लेकर कमर कस ली है। गौतमबुद्ध प्रशासन ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

इसके अनुसार किसी भी जगह 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके साथ ही बिना प्रशासन की अनुमति के कोई धार्मिक रैली आदि नहीं निकाली जा सकेगी।

इन गतिविधियों पर भी रहेगी रोक

सार्वजनिक जगहों पर अनधिकृत रैली निकालना

सार्वजनकि जगहों पर धार्मिक सभा आयोजन करना

सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना

इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के आसपास प्राइवेट ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी

अन्य इलाकों में भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत होगी।

धारा 144 अब हुई धारा 187

गौरतलब है कि बीते सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले तीन संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब भारतीय दंड संहिता IPC (1860) अब भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC (1898) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे।

इसी के तहत अब अपराधों की धाराएं भी बदल गई हैं। इसमें धारा 144 भी आती है जो 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकती है। अब यह धारा 187 हो गई है।

73 साल का बुजुर्ग मिला कोरोना संक्रमित, जिले में एक्टिव मामलों की संख्या तीन पहुंची

गाजियाबाद में शनिवार को एक ओर कोरोना संक्रमण का मामला आया है। संक्रमित की आयु 73 वर्ष है जो वैशाली के निवासी हैं। उन्हें परिवार के लोग खांसी और जुकाम होने पर निजी अस्पताल ले गए थे जहां उनका कोरोना टेस्ट करवाया। जांच के बाद आई रिपोर्ट में उन्हें कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर होम आइसोलेशन में रखा गया है।

गाजियाबाद। शनिवार को जिले में एक ओर कोरोना संक्रमण का मामला आया है। संक्रमित की आयु 73 वर्ष है, जो वैशाली के निवासी हैं। उन्हें परिवार के लोग खांसी और जुकाम होने पर निजी अस्पताल ले गए थे, जहां उनका कोरोना टेस्ट करवाया। जांच के बाद आई रिपोर्ट में उन्हें कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उनकी निगरानी की जा रही है। अब जिले में तीन कोरोना संक्रमित मरीज हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता के अनुसार शनिवार को 60 मरीजों की कोरोना जांच कराई गई, जिनमें एक संक्रमित मिला है। उन्होंने बताया सक्रिय तीनों मरीजों की हालत सामान्य है।

ताक पर डीएम के आदेश, ठंड में ठिठुरते स्कूल पहुंचे नौनिहाल

साहिबाबाद। कड़ाके की ठंड के कारण जिलाधिकारी ने बृहस्पतिवार शाम आठवीं तक के स्कूलों में 29 व 30 दिसंबर को अवकाश घोषित किया था, लेकिन ट्रांस हिंडन के निजी स्कूलों ने जिलाधिकारी के आदेशों की परवाह नहीं की। ज्यादातर स्कूल रोजाना की तरह खुले। ठंड में ठिठुरते नौनिहाल स्कूल पहुंचे।

जिलाधिकारी के आदेश का पालन कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सभी स्कूलों को अवकाश के लिए आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद शुक्रवार को आम्रपाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदिरापुरम, जेकेजी इंटरनेशनल स्कूल, डीपीएस इंदिरापुरम जैसे बड़े स्कूलों में कक्षाएं आयोजित की गईं। जेकेजी से बच्चे को लेकर लौटते अभिभावकों ने बताया कि स्कूलों के अवकाश से संबंधित सरकारी पत्र रात को व्हाट्सएप ग्रुपों पर चल रहा था, लेकिन स्कूल से कोई संदेश नहीं मिला। ऐसे में सुबह बच्चों को स्कूल भेजना पड़ा। वहीं, स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि देर शाम बेसिक शिक्षा अधिकारी का पत्र मिला। ऐसे में रात में सभी अभिभावकों तक मैसेज पहुंचाना मुश्किल था, जिसकी वजह से बच्चे शुक्रवार की सुबह स्कूल पहुंचे। प्रधानाचार्य निधि गौड़ ने बताया कि 30 दिसंबर के अवकाश की सूचना अभिभावकों को दे दी गई है।

57 किलो भार वर्ग में शंभूदयाल की मीनाक्षी ने बाजी मारी

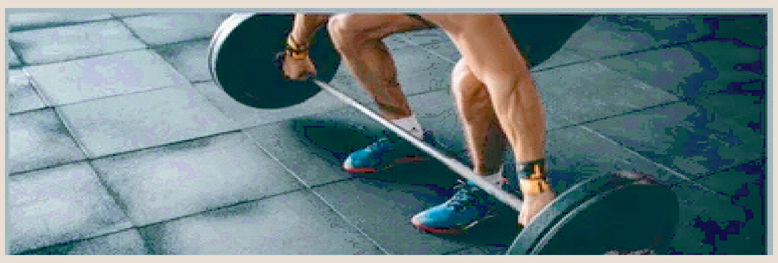

गाजियाबाद। एमएमएच कॉलेज में चल रही सीसीएसयू की दो दिवसीय अंतरविद्यालयीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। इसमें 57 किलो भार वर्ग में शंभूदयाल कॉलेज की मीनाक्षी ने पहला स्थान प्राप्त किया। विजेता खिलाड़ियों को प्राचार्य डॉ. पीयूष चौहान ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया।

47 किलो ग्राम भार वर्ग में डीजे कॉलेज बड़ौत की आरती कुशवाहा ने पहला, इसी कॉलेज की सोनम ने दूसरा व एमएम कॉलेज मोदीनगर की छात्रा अंशिका ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 52 किलो भार वर्ग में एएस कॉलेज मवाना मेरठ की छात्रा दुर्गेश ने पहला व डीजे कॉलेज बड़ौत की छात्रा कामिनी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। 57 किलो भार वर्ग में शंभूदयाल की छात्रा मीनाक्षी ने पहला, डीजे कॉलेज बड़ौत की पायल ने दूसरा व एचएलएम कॉलेज की सपना भारती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 63 किलो भार वर्ग में आरवीएचईआईटी दादरी की साक्षी ने पहला, आरआईटी मेरठ की कृतिका सिंह ने दूसरा, एसएनजीआई मेरठ की ईशाली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

69 किलो भार वर्ग में एसएनजीआई मेरठ की रिया कौशिक ने पहला, एकेपी कॉलेज हापुड़ की सुहानी ने दूसरा व एनसीपीई दादरी की प्राची राना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 76 किलो भार वर्ग में एसएनजीआई की छात्रा साक्षी ने पहला, एमएमएच की मुस्कान ने दूसरा व डीजे कॉलेज बड़ौत की विजेता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीसीएसयू से आए निर्णायक मंडल ने सभी विजेता छात्रों के नामों की घोषणा की। कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉ. कुमुदेश कुमार ने बताया कि शनिवार को बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें 20 से ज्यादा कॉलेजों के छात्र हिस्सा लेंगे।

अलीगढ़ कॉरिडोर बनाने वाली कंपनी के निदेशक से 12.75 लाख की धोखाधड़ी

साहिबाबाद। अलीगढ़ में फ्रंट कॉरिडोर बनाने वाली स्काई लाइन प्रमोटर्स फर्म के निदेशक इंद्रजीत सिंह सालवान ने लिंकरोड थाने में तीन लोगों खिलाफ 12.75 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपियों ने लोनी के चिकंबरपुर पगरना में प्लॉट के फर्जी दस्तावेज से धोखाधड़ी की।

मेरठ के गुरुनानक नगर में रहने वाले इंद्रजीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें अनिरुद्ध कुमार के जरिए अलीगढ़ में फ्रंट कॉरिडोर बनाने का ठेका मिला था। उसने ही इंद्रपाल नाम के व्यक्ति से पहचान कराई जो कॉरिडोर के निर्माण में पानी के टैंकर लाने का काम करने लगा। आरोप है कि अनिरुद्ध और इंद्रपाल और मनोज पंवार ने उन्हें चिकंबरपुर में प्लॉट बिकाऊ होने की जानकारी दी। मनोज ने खुद को प्लॉट का मालिक बताया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर 12.75 लाख रुपये में इंद्रजीत से सौदा तय किया। रकम खाते में जमा करा ली। कई दिन तक आरोपी इंद्रजीत को प्लॉट पर लेकर नहीं गए। बाद में संपत्ति विवादित होने की जानकारी मिली। एसीपी रजनीश उपाध्याय का कहना है कि कागजात और लेनदेन के प्रमाण की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कराने के लिए साथी ने दिए थे 80 हजार रुपये

गाजियाबाद। दुहाई में 23 दिसंबर की सुबह प्रॉपर्टी डीलर मोहित त्यागी की हत्या के मकसद से उनके कार्यालय पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना का मधुबन बापूधाम पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मोहित त्यागी के साथी सन्नी त्यागी ने प्रॉपर्टी के विवाद में उसकी हत्या करने की साजिश रची और वारदात को अंजाम देने के लिए दो बदमाशों को 80 हजार रुपये दिए। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है।

एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए बदमाश हापुड़ के सिंभावली के गांव फरीदपुर गौसाई निवासी कपिल गिरी और बुलंदशहर के फतेहपुर अगौता निवासी यतेंद्र सिंह हैं। यतेंद्र हाल में गौतमबुद्धनगर के सेक्टर135 वालिदपुर में रहता है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने मोहित की हत्या करने के लिए उसके कार्यालय पर चार राउंड फायरिंग की थी।

वारदात को अंजाम देने के लिए दुहाई के रहने वाले सन्नी ने उन्हें पिस्टल और 80 हजार रुपये दिए थे। 40 हजार रुपये वारदात से पहले और 40 हजार रुपये वारदात के बाद दिए थे। फायरिंग के बाद उन्होंने पिस्टल सन्नी को ही दे दी थी। कपिल टिहरी बेचने का काम करता था और यतेंद्र चालक है। एसीपी ने बताया कि मुख्य आरोपी सन्नी की तलाश की जा रही है। उसके पकड़े जाने पर अन्य जानकारी का पता चलेगा। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में बढ़ता धार्मिक पर्यटन एवं उत्पादों का उपभोग भारत के आर्थिक विकास को दे रहा गति

प्रह्लाद सबनानी

उत्तर प्रदेश राज्य आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेक्स्टायल उत्पादन करने वाला राज्य भी बन गया है। राष्ट्रीय उत्पादन में उत्तरप्रदेश राज्य का योगदान बढ़कर 13.24 प्रतिशत हो गया है। उत्तरप्रदेश राज्य में आज 250,000 लाख के आसपास हैंडलूम बुनकर एवं 421,000 पावरलूम बुनकर कार्य कर रहे हैं।

भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार को गति देने में कुछ राज्यों का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही के समय में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, गुजरात एवं राजस्थान जैसे राज्यों की आर्थिक विकास की गति तेज हुई है, जिससे यह राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का बनाने में विशेष योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, एवं कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्यों का योगदान भी नकारा नहीं जा सकता है, परंतु इन राज्यों के आर्थिक विकास की दर तुलनात्मक रूप से कुछ स्थिर सी रही है अथवा कुछ कम हुई है।

समस्त राज्यों के बीच तमिलनाडु एवं गुजरात राज्यों को पीछे धकेलते हुए उत्तरप्रदेश अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। भारतीय अर्थव्यस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2 प्रतिशत का हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार आज 3.7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है। इसमें महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा 15.7 प्रतिशत है। उत्तरप्रदेश राज्य का हिस्सा 9.2 प्रतिशत, तमिलनाडु राज्य का 9.1 प्रतिशत, गुजरात राज्य का 8.2 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल राज्य का 7.5 प्रतिशत है। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर पूर्वी राज्यों एवं जम्मू कश्मीर के बाद बिहार का भी काफी कम योगदान अर्थात केवल 3.7 प्रतिशत दिखाई पड़ता है, जबकि बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है। बिहार को आर्थिक विकास की दृष्टि से आज भी पिछड़ा राज्य कहा जा रहा है। पूर्व के बीमारु राज्यों की श्रेणी से उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान राज्य बाहर आ चुके हैं जबकि बिहार राज्य आज भी इसी श्रेणी में अटका हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 41,720 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, तमिलनाडु राज्य का आकार 27,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, गुजरात राज्य का आकार 26540 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, उत्तरप्रदेश राज्य का आकार 26,510 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, कर्नाटक राज्य का आकार 26,350 करोड़ अमेरिकी डॉलर था और पश्चिम बंगाल राज्य का आकार 18,310 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। पिछले कुछ वर्षों से चूंकि उत्तरप्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर सबसे तेज बनी हुई है अतः आज उत्तरप्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार भारत में दूसरे स्थान पर आ गया है। उत्तरप्रदेश ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को वर्ष 2027 तक एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जबकि, महाराष्ट्र भी अपने राज्य को वर्ष 2028 तक एक लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। इस दृष्टि से अब उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों के बीच इस संदर्भ में आपस में प्रतियोगिता चल रही है।

महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या 11 से 12 करोड़ के बीच है जबकि उत्तरप्रदेश राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। इस दृष्टि से उत्तरप्रदेश राज्य लाभप्रद स्थिति में दिखाई दे रहा है क्योंकि विभिन्न उत्पादों के उपभोग की अधिक गुंजाइश उत्तरप्रदेश राज्य में हैं एवं देश में आज उत्तरप्रदेश राज्य तेजी से विनिर्माण क्षेत्र का हब बनता जा रहा है तथा उत्तरप्रदेश राज्य में धार्मिक पर्यटन भी बहुत तेज गति से विकसित हो रहा है। विशेष रूप से अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटन को भी आकर्षित करता दिखाई दे रहा है। इससे उत्तरप्रदेश राज्य में रोजगार के नए अवसर भी भारी मात्रा में निर्मित हो रहे हैं। अतः उत्पादों के उपभोग के मामले में उत्तरप्रदेश राज्य के साथ किसी भी अन्य राज्य की प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती हैं। आज उत्तरप्रदेश राज्य के नागरिक रोजगार हेतु अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उत्तरप्रदेश राज्य में ही रोजगार के पर्याप्त नए अवसर निर्मित होने लगे हैं। उत्तरप्रदेश राज्य में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज राज्य सरकार भी भारी मात्रा में पूंजी निवेश कर रही है।

निर्यात के क्षेत्र में भी उत्तरप्रदेश राज्य नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तरप्रदेश राज्य के राज्य निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तरप्रदेश राज्य से 84,000 करोड़ रुपए की राशि का निर्यात किया गया था जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुगना होकर 174,000 करोड़ रुपए का हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तरप्रदेश राज्य ने 2 लाख करोड़ रुपए की राशि का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तरप्रदेश राज्य से सबसे अधिक निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, दूरसंचार उपकरण, कृत्रिम फाइबर, गेहूं, चावल, कपास, कालीन एवं हस्तशिल्प जैसे उत्पाद शामिल हैं।

दूसरे, उत्तरप्रदेश राज्य आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा टेक्स्टायल उत्पादन करने वाला राज्य भी बन गया है। राष्ट्रीय उत्पादन में उत्तरप्रदेश राज्य का योगदान बढ़कर 13.24 प्रतिशत हो गया है। उत्तरप्रदेश राज्य में आज 250,000 लाख के आसपास हैंडलूम बुनकर एवं 421,000 पावरलूम बुनकर कार्य कर रहे हैं। चूंकि कपड़ा उद्योग कम पूंजी निवेश के साथ अधिक मानवीय आधारित उद्योग है, अतः इस क्षेत्र में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर एवं लखनऊ उन्नाव कानपुर क्षेत्र में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कलस्टर भी स्थापित किये जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में विनिर्माण इकाईयां स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं।

विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं में प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षणों में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इन प्रदेशों की अनुमानित आर्थिक प्रगति की दर को दर्शाया गया है। उत्तरप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक प्रगति की दर 16.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है, इसी प्रकार मध्यप्रदेश में 16.34 प्रतिशत, राजस्थान में 16.4 प्रतिशत, गुजरात में 15.5 प्रतिशत, तेलंगाना में 15.6 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 6.8 प्रतिशत, तमिलनाडु में 8.19 प्रतिशत, बिहार में 9.7 प्रतिशत, कर्नाटक में 7.9 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 19 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कुल मिलाकर भारत के समस्त प्रदेशों के बीच उत्तरप्रदेश राज्य आज आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे कुछ अन्य राज्य भी विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन राज्यों की आर्थिक नीतियां देशी एवं विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इस प्रकार यह समस्त राज्य मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर ले जाने में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यदि बिहार जैसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगाना की तर्ज पर एवं पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर पूर्वी राज्य जैसे अन्य छोटे राज्य भी अपने राज्यों में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में सफल होते हैं तो शीघ्र ही भारत की आर्थिक विकास की दर को 10 प्रतिशत के पार पहुंचाया जा सकता है।

ईवी स्टार्ट-अप Creatara ने पेश किया VS4 और VM4 कॉन्सेप्ट, जानें इनमें क्या दी गई हैं खूबियां

ईवी स्टार्ट–अप Creatara ने हाल ही में अपने ईवी कॉन्सेप्ट से पर्दा हटाया है। स्टार्ट–अप के द्वारा VS4 और VM4 को पेश किया गया है। कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को पेश करते हुए बताया है कि यह स्कूटर मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। इनमें दी गई एडवांस तकनीक इन्हें बाजार में पहले से मौजूद स्कूटर से अलग बनाती है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों को खूब तरजीह दे रहे हैं। वहीं इस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कंपनियां भी खूब वाहन लॉन्च कर रही हैं। इसी कड़ी में अब Creatara नाम के एक ईवी स्टार्ट-अप ने अपने व्हीकल कॉन्सेप्ट का अनावरण किया है। जो कि VS4 और VM4 है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर हैं आधारित

कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को पेश करते हुए बताया है कि यह स्कूटर मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इनमें सेफ्टी कस्टमाइजेशन और सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया गया है, इनमें दी गई एडवांस तकनीक इन्हें बाजार में पहले से मौजूद स्कूटर से अलग बनाती है।

बैटरी रेंज और टॉप स्पीड

ईवी स्टार्ट-अप की तरफ से दावा किया गया है कि ये दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर महज 3.4 सेकंड के भीतर ही 0 से 40 किमी की रफ्तार पकड़ लेते हैं। इनमें दी गई बैटरी सिंगल चार्जिंग में 100 किमी की रेंज देने का सामर्थ्य रखती हैं और इनकी टॉप स्पीड भी 100 किमी/प्रतिघंटा है।

सेफ्टी मानकों पर कैसा है स्कूटर?

क्रिएटारा (Creatara) के द्वारा इन स्कूटरों को सेफ्टी मानकों के हिसाब से सबसे बेहतर बताया है। कहा गया इन्हें सुरक्षित स्टार्ट तकनीक के साथ भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। कंपनी ने दावा किया है कि इन्हें पूरी तरह से आम आदमी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। मुश्किल इलाकों में सुचारू रुप से चलाने के लिए इसमें हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल जैसी खूबियां दी जाएंगी।

होंडा के सबसे अधिक बिकने वाले स्कूटर Activa 6G में क्या कुछ खास, यहां पढ़ें अधिक डिटेल्स

Honda Activa 6g इस स्कूटर में कुल blue red yellow black white और grey का कलर ऑप्शन मिलता है।भारतीय बाजार में activa की सेल काफी अधिक रही है। ये होंडा का सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल है। इस स्कूटर में कई वेरिएंट मिलते हैं।नवंबर की ही बात करें तो इस स्कूटर की कुल 196055 यूनिट्स सेल हुई है। यह कंपनी का नए जनरेशन का स्कूटर है।

नई दिल्ली। इन दिनों मार्केट में कई तरह के स्कूटर्स मौजूद है और लोग आज के समय में स्मार्ट स्कूटर ही खरीदना पसंद करते हैं। आज के समय में मार्केट में कई शानदार स्कूटर मौजूद है। मार्केट में किफायती कीतम में कई पेट्रोल वाले स्कूटर मौजूद है जो अच्छी माइलेज भी देते हैं।

इस खबर के माध्यम से आज हम आपके लिए एक शानदार स्कूटर की जानकारी लेकर आए हैं। जो लुक वाइज भी स्टाइलिश है, मोबाइल कनेक्टिविटी और डिस्क ब्रेक भी मिलता है। हम बात Honda Activa 6G की कर रहे हैं। चलिए आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी देते हैं।

Honda Activa सेल्स

भारतीय बाजार में activa की सेल काफी अधिक रही है। ये होंडा का सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल है। इस स्कूटर में कई वेरिएंट मिलते हैं। बीते नवंबर की ही बात करें तो इस स्कूटर की कुल 196055 यूनिट्स सेल हुई है। वहीं नवंबर 2022 में इसकी कुल 175084 यूनिट्स की सेल हुई थी।

Honda Activa 6G

यह कंपनी की नई जनरेशन की स्कूटर है। इसमें कुल 9 वेरिएंट मिलते हैं। इस स्कूटर में 109.51 सीसी का इंजन मिलता है। वहीं पेट्रोल स्कूटर में कुल 5.3 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी भी मिलता है। इस स्कूटर में ट्यूबलेस टायर भी मिलता है। ये स्कूटर 47 kmpl तक की माइलेज देता है। ये एक हाई स्पीड स्कूटर है। इसमें 85 Kmph की टॉप स्पीड मिलती है।

कलर ऑप्शन

इस स्कूटर में कुल blue, red, yellow, black, white और grey का कलर ऑप्शन मिलता है। ये स्कूटर 7.73 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 74,536 रुपये है। इसके दोनों टायरों में ड्रम ब्रेक मिलता है। इसके साथ ही इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। जिसके कारण तेज रफ्तार में ब्रेक लगाने पर स्कूटर को कंट्रोल करना आसान होता है।

Citroen की कार नए साल से होगी महंगी, 31,800 रुपये तक का हुआ इजाफा

सिट्रोन (Citroen) की कार खरीदना 1 जनवरी 2024 से महंगा हो जाएगा। कार बनाने वाली कंपनी ने बताया कि उसने अपनी कारों की कीमत में 31800 रुपये तक का इजाफा किया है। कंपनी सबसे अधिक कीमत सिट्रोन eC3 की बढ़ाएगी। इसके एंट्री लेवल लाइव वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट में 31800 रुपये की समान बढ़ोतरी की होगी। इसकी कीमत 5.98 लाख रुपये से शुरू है।

नई दिल्ली। फ्रांस की वाहन निर्माता कंपनी सिट्रोन (Citroen) की कार खरीदना 1 जनवरी, 2024 से महंगा हो जाएगा। कार बनाने वाली कंपनी ने बताया कि उसने अपनी कारों की कीमत में 31,800 रुपये तक का इजाफा किया है। कंपनी ने अभी सिट्रोन C3, न्यू C3 एयरक्रॉस SUV, न्यू eC3 ऑल इलेक्ट्रिक और C5 एयरक्रॉस एसयूवी शामिल है।

कीमत में हुई बढ़ोतरी

कंपनी सबसे अधिक कीमत सिट्रोन eC3 की बढ़ाएगी। इसके एंट्री लेवल लाइव वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट में 31,800 रुपये की समान बढ़ोतरी की होगी। यही कीमतें C3 एयरक्रॉस के लिए भी सामान्य होंगी। वहीं इसके वेरिएंट You 1.2 5S को छोड़कर सभी वेरिएंट में 20,800 रुपये का इजाफा किया जाएगा।

इसके साथ ही सिट्रोन C3 की 1 जनवरी से इसके शाइन वेरिएंट के लिए आपको 15,800 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं अन्य सभी वेरिएंट की कीमतों में 18 हजार रुपये तक का इजाफा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि इसकी कीमत 5.98 लाख रुपये से शुरू है।

कंपनी की आने वाली कार सिट्रोन C3X

वाहन निर्माता कंपनी इस कार में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकती है। इसके इंजन को 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें एक 6 स्पीड टॉर्क कनवर्टर यूनिट भी मिलता है। इसके अलावा कंपनी इसमें हाइब्रिड इंजन भी दे सकती है।

क्योंकि हाइब्रिड कारों को इस समय मार्केट में काफी अधिक पसंद किया जा रहा है। इसमें फीचर्स के तौर पर 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एपल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, स्प्लिट हेडलैंप, नए रैप अराउंड LED टेल लाइट्स, डुअल-टोन अलॉय व्हील, ब्लैक-आउट बी-पिलर, डुअल एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर भी मिल सकता है।

शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आती है ये ऑफ रोडिंग कारें, कीमत 10 लाख से शुरू

ऑफ रोडिंग कार को चलाने में काफी अच्छा लगता है। इनकी राइडिंग एक्सपीरियंस काफी अलग ही होती है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। हमारी लिस्ट में ऑफ रोडिंग के लिए इसुजु वी–क्रॉस है। ये एक शानदार एसयूवी है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 225 मिमी है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 22.07 लाख रुपये से लेकर 27 लाख रुपये तक जाती है।

नई दिल्ली। क्या आप अपने लिए एक नई ऑफ रोडिंग कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी शानदार लुक के साथ आने वाली तो आज हम आपके लिए भारतीय बाजार में मौजूद ऑफ रोडिंग कारों की लिस्ट लेकर आए हैं। ऑफ रोडिंग कार को चलाने में काफी अच्छा लगता है। इनका राइडिंग एक्सपीरियंस काफी अलग ही होता है। चलिए आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी देते हैं।

Citroen C5 Aircross SUV

भारतीय बाजार में सिट्रोएन सी5 एयरक्रॉस एसयूवी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। इस कार का ग्राउंड क्लीयरेंस 230 मिमी का है। मार्केट में इस कार की कीमत 37.17 लाख रुपये एक्स शोरूम है।

Mahindra Thar

मार्केट में ये कार ऑफ रोडिंग के लिए ही जानी जाती है। थार आज से ही नहीं ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है। ये कई समय से लोगों के दिलो पर राज कर रही है। इस कार की ग्राउंड क्लीयरेंस 226 मिमी है। इस कार की एक्स शोरुम कीमत 10.54 लाख रुपये से शुरू है जो 16.78 लाख रुपये तक जाती है।

Isuzu V-Cross

हमारी लिस्ट में ऑफ रोडिंग के लिए इसुजु वी-क्रॉस है। ये एक शानदार एसयूवी है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 225 मिमी है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 22.07 लाख रुपये से लेकर 27 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।

Toyota Fortuner

टोयोटा फॉर्च्यूनर भारतीय बाजार में लोगों की फेवरेट एसयूवी में से एक है। इस कार में 220 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 32.99 लाख रुपये से शुरू होती है जो 50.74 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है।

Honda elevate

भारतीय बाजार में ये कार इसी साल लॉन्च हुई है। आते ही इस कार की डिमांड मार्केट में काफी तेजी से बढ़ गई। इस कार की ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिमी है। इस कार की कीमत 11 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 16 लाख रुपये तक जाती है।

क्या अमरीका में लोकतंत्र खतरे में है?

भानु धमीजा

अमरीका को ऐसे किसी भी संवैधानिक बदलाव से बचना चाहिए जो शक्तियों के इस सुंदर संतुलन को बदले। अमरीकी सिस्टम की कुछ विशेषताओं पर अकसर 'अलोकतांत्रिक' होने के रूप में हमला किया जाता है। जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज, सेनेट का सभी राज्यों को समान वोट और फिलिबस्टर नियम। परंतु उन्हें खत्म करने से सरकार की शक्तियां कुछ ही हाथों में समाहित हो जाएंगी। विश्वास बनाए रखो, अमरीका। आपका लोकतंत्र बिल्कुल सही चल रहा है'

आश्चर्यजनक रूप से 83 प्रतिशत अमरीकियों का मानना है कि उनके देश का लोकतंत्र खतरे में है। राष्ट्रपति बाइडेन बार-बार याद दिलाते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। ट्रंप बाइडेन के बारे में भी यही बात कहते हैं। और एक हालिया सर्वेक्षण में, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के बहुमत का कहना है कि 'लोकतंत्र पतन के खतरे में है।'

परंतु जमीन पर कुछ और ही कहानी सामने आती है। अमरीकी चुनाव ठीक से और समय पर हो रहे हैं, उनमें नागरिकों की भागीदारी दर ऊंची है, देश के राज्य और संघीय प्रशासन स्थिर हैं और संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं। सभी स्थानीय सरकारी निकाय – लगभग 80,000 नगर परिषदों से लेकर शिक्षा बोर्ड तक – और सभी 50 राज्य सरकारें अपने निर्दिष्ट कत्तव्यों का पालन कर रही हैं और लोगों के प्रति जवाबदेह हैं।

यदि वर्जीनिया, ओहायो और केंटकी में हाल के चुनाव हमें कुछ बताते हैं तो वह यह है कि अमरीकी लोकतंत्र अत्यधिक संवेदनशील है। डेमोक्रेट्स ने बड़ी जीत हासिल की – बावजूद इसके कि बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग घटकर 40 प्रतिशत के करीब रह गई है – ज्यादातर इसलिए क्योंकि पार्टी का गर्भपात समर्थक एजेंडा वही है जो लोग चाहते हैं।

संघीय स्तर पर, जहां इस लोकतंत्र के खतरे की चर्चा का अधिकांश ध्यान केंद्रित है, अमरीका की तीनों शाखाएं उसी तरह काम कर रही हैं जैसे वे 235 वर्षों से कर रही थीं। कांग्रेस ने पिछले साल पांच महत्त्वपूर्ण कानून पारित किए, जिनमें से अधिकांश को द्विदलीय समर्थन प्राप्त था। इसने जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की, राष्ट्रपति चुनावों में सुधार किया, हथियार कानूनों को कड़ा किया, चीन के खिलाफ अमरीकी विनिर्माण को मजबूत किया, और राष्ट्रीय स्तर पर समलैंगिक विवाह को प्रतिष्ठित किया। इस वर्ष, रिपब्लिकन नियंत्रित सदन, डेमोक्रेट-नियंत्रित सीनेट और राष्ट्रपति पद उसी प्रकार एक-दूसरे से द्वंद्व कर रहे हैं जैसा कि वे हमेशा विभाजित सरकार की अमरीका की अनूठी प्रणाली के तहत करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय भी दूरगामी निर्णय करना जारी रखे है। हाल ही में इसने सकारात्मक कार्रवाई कर राज्य के अधिकारों को सुदृढ़ किया और कार्यकारी अधिकारों पर रोक लगाई।

जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, अमरीकी प्रणाली के अंतर्निहित संवैधानिक सुरक्षा उपायों ने उनसे काफी प्रभावी ढंग से निपटा। पद संभालने के दो साल के भीतर ही उनके पंख काट दिए गए जब डेमोक्रेट्स ने 2018 के मध्यावधि चुनाव में सदन में बहुमत हासिल कर लिया। अपने कार्यकाल के आखिरी दो वर्षों में, ट्रंप जांच और दो महाभियोगों के कारण अपंग हो गए। और उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद अब तक उन पर चार आपराधिक मामलों में 91 आरोपों पर अभियोग दाग दिए गए हैं।

ट्रंप के सत्ता अतिक्रमण करने या एकतरफा कार्रवाई करने के प्रयासों को अमरीका के संविधान की प्रसिद्ध नियंत्रण और संतुलन प्रणाली ने रोक दिया। उदाहरण के लिए, कुछ मुस्लिम देशों से आप्रवासन पर उनका प्रतिबंध, और बच्चों को दस्तावेज न होने पर उनके अप्रवासी माता-पिता से अलग करने की उनकी नीति, दोनों को अदालतों द्वारा रोक दिया गया था। दक्षिणी सीमा पर दीवार बनाने के उनके प्रयास को ही कांग्रेस ने विफल कर दिया।

यहां तक कि 'हाउ डेमोक्रेसीज डाई' पुस्तक के लेखकों ने भी स्वीकार किया कि अपने पहले वर्ष में, 'राष्ट्रपति ट्रंप एक लापरवाह ड्राइवर की तरह बार-बार रेलिंग से टकराए, लेकिन वह उसे नहीं तोड़ पाए। हमने तानाशाही की सीमा पार नहीं की।'

लेकिन फिर भी डराने वाले अमेरिकी लोकतंत्र के खात्मे की चेतावनी देते हैं। वर्तमान में यह बार-बार ट्रंप के 'बड़े झूठ' (कि बाइडेन की जीत नाजायज थी) और कैपिटल पर 6 जनवरी के हमले के लिए उनके उकसावे के रूप में किया जाता है। लेकिन ट्रंप इन चालों में भी विफल रहे। लगभग सभी राज्य और संघीय निर्वाचित अधिकारी – जिनमें कई रिपब्लिकन और उनके अपने उपराष्ट्रपति भी शामिल हैं – अपनी संवैधानिक शपथों के प्रति सच्चे रहे और पद पर बने रहने के उनके प्रयासों को सफल बनाने से इनकार कर दिया।

फिर भी विनाश के ये भविष्यवक्ता अमरीकी लोकतंत्र को बदनाम करना जारी रखे हैं, क्योंकि इससे उनकी पार्टी को लाभ मिलता है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को उन्हें और उनकी पार्टी को देश के लिए खतरे के रूप में चित्रित करने को भरपूर ईंधन दिया है। इससे वामपंथी राजनेताओं, लेखकों और कार्यकर्ता समूहों को अपने विचारों को बेचने का एक आकर्षक तंत्र तैयार हो गया है।

परंतु यह केवल ध्रुवीकरण को बढ़ाने और अमरीकी लोकतंत्र में विश्वास को कमजोर करने का काम करता है। ताजा शोध से पता चलता है कि अमरीकी तब अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं जब उन्हें डर होता है कि विरोधी पार्टी भी ऐसा ही कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक जेसन विलिक ने हाल ही में 'वाशिंगटन पोस्ट' के कॉलम में तर्क दिया, 'अमरीकी लोकतंत्र के लिए खतरा, कम से कम आंशिक रूप से, बुरी जानकारी से उत्पन्न होता है। लोग अन्य पार्टियों से लोकतंत्र के खतरे को अधिक महत्त्व देते हैं और परिणामस्वरूप रक्षात्मक रूप से लोकतांत्रिक मानदंडों को नष्ट करने के अधिक इच्छुक हो जाते हैं।'

अमरीका में लोकतंत्र तब तक खतरे में नहीं है जब तक यह अपने संस्थापकों की संवैधानिक संरचना को बरकरार रखते हैं। यह शक्तियों के एकीकरण को सरलता से प्रतिबंधित करती है। संघीय व्यवस्था, कार्यकारी और विधायी शक्तियों का पृथक्करण और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति पिछली दो शताब्दियों से अमरीका की सफलता की महत्त्वपूर्ण कुंजी रहे हैं।

जस्टिस एंटोनिन स्कैलिया ने 2014 के एक साक्षात्कार में कहा, 'आज दुनिया का हर तानाशाह जनता के अधिकारों का वास्ता देता है।' परंतु यह कागजी अधिकार नहीं जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पैदा करते हैं। यह सरकार की संरचना है जो किसी को भी संपूर्ण शक्ति जब्त करने से रोकती है। जो लोकतंत्र को मजबूत रखती है।

अमरीका को ऐसे किसी भी संवैधानिक बदलाव से बचना चाहिए जो शक्तियों के इस सुंदर संतुलन को बदले। अमरीकी सिस्टम की कुछ विशेषताओं पर अकसर 'अलोकतांत्रिक' होने के रूप में हमला किया जाता है। जैसे कि इलेक्टोरल कॉलेज, सेनेट का सभी राज्यों को समान वोट और फिलिबस्टर नियम। परंतु उन्हें खत्म करने से सरकार की शक्तियां कुछ ही हाथों में समाहित हो जाएंगी। विश्वास बनाए रखो, अमरीका। आपका लोकतंत्र बिल्कुल सही चल रहा है।

–अमरीका में 'द हिल' में प्रकाशित

आश्चर्यजनक रूप से 83 प्रतिशत अमरीकियों का मानना है कि उनके देश का लोकतंत्र खतरे में है। राष्ट्रपति बाइडेन बार-बार याद दिलाते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। ट्रंप बाइडेन के बारे में भी यही बात कहते हैं। और एक हालिया सर्वेक्षण में, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के बहुमत का कहना है कि 'लोकतंत्र पतन के खतरे में है।'

संपादक की कलम से

मौत के बजाय कारावास

कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा-ए-मौत रद्द कर दी गई है। उन्हें अब कारावास की सजा दी गई है। वह सजा कितने साल की होगी, यह अदालत के विस्तृत फैसले से ही स्पष्ट होगा। यह अदालती फैसला भारत और उसके पूर्व नौसैनिकों के लिए सुखद और राहतपूर्ण है, क्योंकि जासूसी के अपुष्ट आरोपों पर भारतीय विदेशों में जेल की सजाएं झेलते रहे हैं। कतर में मौत की सजा ने भारत को हैरानी के साथ-साथ सदमे में भी डाल दिया था। कतर के सरकारी अफसर अपराध का खुलासा नहीं कर रहे थे और न ही आरोपों को सार्वजनिक कर रहे थे। यह आरोप जरूर सामने आया कि पूर्व नौसैनिकों ने कतर की एक महत्त्वपूर्ण पनडुब्बी परियोजना की संवेदनशील सूचना इजरायल को दी थी। मौजूदा संदर्भों में भारत इजरायल का मित्र-देश है, जबकि कतर हमास के सियासी नेतृत्व की आर्थिक मदद करता रहा है और उन्हें पनाह भी देता रहा है, लेकिन पनडुब्बी वाली सूचना को लेकर कतर के आरोपों का आधार पुख्ता नहीं था और न ही साक्ष्य थे। बहरहाल भारत की कूटनीतिक और कानूनी लड़ाई रंग लाई और 8 भारतीय मौत की सजा से बच गए। भारत और कतर के दरमियान 2015 का एक समझौता है, जिसके तहत सजायाफ्ता लोगों को उनके गृह देश में ही स्थानांतरित करने का प्रावधान है। वे शेष सजा अपने ही देश में काट सकते हैं। मौजूदा मामले में क्या होता है, उसका खुलासा आने वाले दिनों में ही होगा। गौरतलब यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की दुबई में मुलाकात पर्यावरण के कॉप-28 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। प्रधानमंत्री ने पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी और सजा-ए-मौत का जिक्र किया था अथवा नहीं, सरकार उसे लेकर बिल्कुल खामोश है।

अगस्त, 2022 में भारत के पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें एकांत कारावास में रखा गया था और मामले को पूरी तरह 'गोपनीय' बना दिया गया था। दोनों ही सरकारों ने आरोपों पर सार्वजनिक बातचीत करने में संकोच बरता। हालांकि कतर में भारत के वाणिज्य दूत और कानूनी टीम को पूर्व नौसैनिकों से मिलने की इजाजत दी गई। कतर में 8 लाख से अधिक भारतीय बसे और काम करते हैं। पूरे पश्चिमी एशिया में भारतीयों की कार्यरत आबादी सर्वाधिक है, लिहाजा जासूसी के आरोप सहज और चुनौतीपूर्ण हैं। पूर्व नौसैनिकों में कैप्टन स्तर के अधिकारी भी हैं, जो ओमान की 'अल दहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी' के लिए काम कर रहे थे। कंपनी कतर की नौसेना को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दे रही थी। हम किसी भी तरह का दावा नहीं कर सकते कि यह रक्षा-कंपनी संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न रही है या उसे 'काली सूची' में डाल देना चाहिए अथवा भारतीय अब भी इस कंपनी में कार्यरत हैं या कंपनी छोड़ चुके हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों में शामिल होने से पहले भारतीयों को विस्तृत जानकारी ले लेनी चाहिए कि उन कंपनियों की पृष्ठभूमि क्या रही है। जिन देशों की न्यायिक व्यवस्था 'ब्लैक बॉक्स' जैसी है, वहां नौकरी नहीं करनी चाहिए। आखिर न्यायिक इंसाफ तो अनिवार्य है। कमोबेश यह मामला भारतीयों को कई बड़े सबक दे सकता है। आज की युवा पीढ़ी वे सबक लेना चाहे अथवा विदेश जाने की अंधी दौड़ में शामिल रहे। फिर भी पश्चिमी एशिया में हमें अपनी सक्रियता और तालमेल, संपर्क को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया ही एक परिवार की तरह है।

चर्चा

क्या वे 'आतंकी घुसपैठिए' हैं

लोकसभा में घुसपैठ करने वाले क्या आतंकवादी हैं? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अदालत में सरकारी वकील ने ऐसे आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस का भी अंदेशा है कि घुसपैठियों की किसी आतंकी साजिश में भूमिका हो सकती है! यदि किसी भी तरह उनके तार आतंकवाद से जुड़े हैं, तो जांच के निष्कर्ष स्पष्ट कर सकते हैं। यह भी संवेदनशील स्थिति है कि कथित आतंकी संसद की दर्शक-दीर्घा तक पहुंच कर लोकसभा की कार्यवाही के बीच छलांग लगाकर सुरक्षा-व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर चुके हैं। क्या अन्य आतंकियों के लिए रास्ता साफ किया जा चुका है? आतंकवाद का कोई निश्चित चेहरा-मोहरा नहीं होता। किसी की गतिविधियों और घुसपैठी करतूतों से ही आतंकवाद की ओर संकेत जाते हैं। चूंकि पुलिस और जांच एजेंसियों ने संसद के घुसपैठियों के खिलाफ 'आतंकवाद रोधी अधिनियम' (यूएपीए) की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है, आपराधिक साजिश, देश को तोडऩे, दंगा फैलाने और लोकसेवकों के काम में बाधा डालने की धाराएं भी लगाई गई हैं, लिहाजा प्रथमदृष्ट्या यह आतंकवाद का मामला लगता है। आरोपितों के काम-धंधे, पढ़ाई और पृष्ठभूमि को देखकर फैसला नहीं लिया जा सकता। यूएपीए कठोरतम कानून है, जिसमें फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके तहत जमानत भी असंभव-सी होती है। फिलहाल अदालत ने 7 दिन की रिमांड दी है, जिसे बढ़ाया जाना प्रक्रिया का ही हिस्सा है।

सवाल है कि यदि आरोपित घुसपैठिए आतंकी हैं, तो वे किस संगठन से जुड़े हैं? किसकी साजिश पर उन्होंने लोकसभा में कूदने और धुआं-धुआं करने जैसा हमलावर रुख अपनाया? यदि वे बीते डेढ़ साल से संसद में घुसकर उत्पात मचाने या सनसनी फैलाने की साजिश पर विमर्श कर रहे थे और देश के अलग-अलग शहरों में मुलाकातें कर रहे थे, तो उनके खर्चे कौन उठा रहा था? कौन फंडिंग कर रहा था उन्हें? सवाल कई हैं और जांच के दौरान उन्हें जरूर खंगाला जाएगा, लेकिन वे 'बेचारे', 'बेरोजगार' और 'भूले-भटके नौजवान' नहीं माने जा सकते। जब कश्मीर में आतंकवाद और जेहाद चरम पर थे, तब भी युवा आतंकियों को 'भूले-भटके' करार दिया जाता था, लेकिन अकेले उस आतंकवाद ने ही करीब 45,000 जिंदगियां छीन ली थीं। पंजाब और पूर्वोत्तर के आतंकवाद या उग्रवाद की तो चर्चा हम कर ही नहीं रहे। यदि ऐसे विशेषण देकर विपक्ष इन घुसपैठियों का बचाव करेगा और माफ करने की पैरवी करेगा, तो निश्चित ही देश में आतंकवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। देश में लाखों-करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और औसत परिवार महंगाई के दंश झेल रहा है, तो इसके मायने ये नहीं हैं कि वे संसद पर ही हमला कर दें! यकीनन ये राष्ट्रीय समस्याएं हैं, लेकिन संसद में घुसपैठ करना तो जघन्य अपराध है। बहरहाल सभी आरोपित सोशल मीडिया पर 'भगत सिंह फैन क्लब' और 'नेताजी सुभाष चंद्र बोस' ग्रुप से जुड़े हैं। बल्कि उन्होंने ऐसा क्रांतिकारी बनने का मुगालता पाल लिया है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को 'अतिवादी नक्सल' चित्रित कर उन्होंने एक और अपराध किया है। देश में अब अंग्रेजों की नहीं, हमारी अपनी लोकतांत्रिक सत्ता है। फिर किस पर 'स्मोक कैन' या 'बम' अथवा 'ग्रेनेड' का इस्तेमाल किया जा रहा है? यदि आप प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के खिलाफ हैं, तो चुनाव आने वाले हैं। उनके खिलाफ जनादेश दिया जा सकता है, लेकिन संसद के खिलाफ साजिश स्वीकार्य नहीं है। इस मुद्दे पर क्षुद्र राजनीति करना और बदले में 13 लोकसभा सांसदों को निलंबित करना अच्छा संसदीय आचरण नहीं है। ब

सेट है नए साल का एजेंडा

राजेंद्र ठाकुर

नए साल में अपन ने क्या नया करना है, यह एजेंडा अब पूरी तरह सेट है। कई कई रातें लगाकर पूरे होशो हवास में ठोक बजाकर यह एजेंडा सेट किया है। अब पूरे 365 दिन इसी एजेंडे पर अमल करना है। क्या मजाल है कि इसमें एक भी आइटम आगे पीछे हो जाए। हमारा यह एजेंडा पर्सनल टाइप का एजेंडा है। यह एजेंडा किसी राजनीतिक दल के एजेंडे की तरह नहीं है और न ही यह चुनावी घोषणा पत्र की तरह है कि उस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं होती। पब्लिक भी पहले बड़े ध्यान से एजेंडा सुनती है और फिर दुनिया भर की उलझनो में मशरूफ हो जाती है। पब्लिक को याद ही नहीं रहता कि कौनसा दल क्या एजेंडा लेकर आया था और क्या कारनामा कर गया। मैं नए साल का एजेंडा दिसंबर महीने की शुरुआत में ही तय करना शुरू कर देता हूं। रजाई में बैठकर घूंट घूंट चाय पीते हुए मैं चारों दिशाओं में अपने दिमाग के घोड़े दौडाता हूं। फिर पास रखी कॉपी में नए-नए आइडिया नोट करता रहता हूं। मुझे नए साल का इंतजार उसी तरह रहता है, जैसे विपक्ष में बैठे लोगों को सत्ता का, सत्ता में बैठे लोगों को कुर्सी का, कुर्सी पर विराजमान लोगों को अपने विरोधियों के सितारे गर्दिश में जाने का और आम आदमी को महंगाई के चक्रव्यूह से छुटकारे का इंतजार रहता है।

ज्यादा विस्तार में जाना हो तो यह कहूंगा कि जिस तरह माफिया सरगनाओं को लीडर के आशीर्वाद का, जुगाड़ू लोगों को सूखे और बाढ़ का, अधिकारियों को मलाईदार पोस्टिंग का और सीबीआई तथा ईडी जैसी एजेंसियों को ऊपर से सिग्नल का इंतजार रहता है, उसी तरह मुझे नए साल का इंतजार रहता है। दिसंबर महीना आते-आते मैं बाकी सारे काम छोडक़र इस मगजमारी में बैठ जाता हूं कि पुराने साल को कैसे किक मारनी है और नए साल का एजेंडा कैसे सेट करना है। मैं पुराने एजेंडा को भी आत्ममंथन के लिए साथ में रख लेता हूं। इससे काफी मदद मिलती है। वैसे भी अपना एजेंडा बड़ा क्लियर सा होता है जिसमें जो भीतर है, वही बाहर है और जो बाहर है, वही भीतर है। नेताओं के एजेंडे की तरह इसमें कोई ऐसा वैसा छुपा हुआ या सीक्रेट एजेंडा नहीं होता। नए साल का जो इस बार मैंने एजेंडा तैयार किया है, वह देश की बुद्धिजीवी जनता के समक्ष रख रहा हूं। इस एजेंडे का फंडा बिल्कुल पारदर्शी है। पिछले साल जिन सौदों में अपुन कमीशन नहीं खा पाए थे, वह कसर इस बार निकालेंगे। बिना कमीशन के कोई सौदा नहीं होगा और कमीशन की दरें क्या होंगी तथा कमीशन किन-किन में बांटा जाएगा, इस बारे में सुझाव देने के लिए एक कमीशन बिठाया जाएगा। जिस तरह मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति के बारे में हर पखवाड़े मुल्क की जनता को बताया जाता है, उसी तरह कमीशन की दरें घटने या बढऩे के बारे में भी पब्लिक को जानकारी दी जाएगी। एक बात और क्लियर है कि पुरानी योजनाओं से अब कोई पैसा नहीं खाया जाएगा, बल्कि नई योजनाओं का दोहन किया जाएगा। नई योजनाओं में संभावनाएं ज्यादा होती हैं। संभावनाओं को अवसर में बदला जाएगा।

अगला एजेंडा यह है कि सत्ता की मलाई खाने में अपनी मित्र मंडली को पूरी तवज्जो दी जाएगी। महत्वपूर्ण सीटों पर मित्रों को बिठाया जाएगा। किसी मित्र को राजनीतिक सलाहकार का ओहदा दिया जाएगा तो किसी मित्र को मीडिया सलाहकार बनाकर फुर्सत में उससे सलाहें ली जाएंगी। जिंदगी में छत्तीस सौ लफड़े होते हैं। हर लफड़े पर अलग-अलग सलाह लेने के लिए अलग-अलग मित्र सलाहकार बनाए जाएंगे और उनको बड़ा रैंक देकर सचिवालय में कमरे अलॉट कर दिए जाएंगे। इन कमरों में बैठकर वे अफसरों को फोन किया करेंगे और अपने सलाहकार होने का रौब दिखाकर अपने काम निकलवाया करेंगे। अगला एजेंडा यह होगा कि विदेश के दौरे किए जाएंगे और वहां आलतू फालतू टाइप के लोगों को इक_ा करके उनके साथ फोटो खिंचवाई जाएगी और फिर पब्लिक को बताया जाएगा कि दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगपति अब निवेश के लिए तैयार कर लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यह रहेगा कि पार्टी के अंदर और पार्टी के भीतर घोषित और अघोषित विरोधियों को डंडा देने के लिए विजिलेंस और अन्य एजेंसियों की सेवाओं का भरपूर सदुपयोग किया जाएगा।

गुरमीत बेदी

चिंतन विचार

बजता है डंका हमारा

हिमाचल में निवेश की दरख्वास्त पर पहरे सख्त हैं, जमीन की आबरू में जंगल की हवा भ्रष्ट है। परियोजनाओं के श्रृंगार में कमोबेश हर सरकार की कसौटियां यह तय नहीं कर पातीं कि आखिर इरादों को जमीं पर उतारने की जमीन है कहां और कौनसे नियम-कानून बाधक हैं। कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का संकल्प कई महीनों से पैमाइश कर रहा है, लेकिन अधिकांश परियोजनाएं कहीं न कहीं प्रस्तावित जमीन पर उलझ रही हैं। इसी से राजनीतिक वैमनस्य तथा सूझबूझ के बीच वर्षों से मुकाबला चल रहा है और अक्सर ऐसी जगह पर तंबू गाड़ दिए जाते हैं, जहां परियोजनाओं का औचित्य ही पूरा नहीं होता। उदाहरण के लिए पर्यटन गांव के लिए पहले धर्मशाला में नरघोटा की वही जमीन खोजी गई, जहां हिमुडा ने उपग्रह शहर बनाने की एक पूरी परियोजना अंतिम चरण तक पहुंचा दी थी। अब यही पर्यटक गांव पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय परिसर की उपलब्ध जमीन पर बसाने की तैयारी है। पहले ही कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर हेलिपोर्ट के लिए भूमि तय है और अगर अनुसंधान-अध्ययन की मिलकीयत से पर्यटक गांव की निशानदेही हो जाती है, तो यह अपनी तरह का अजूबा होगा। हिमाचल का किरदार भी कितना अजीब है और कुछ पाने के लिए सदियां खोने के लिए तैयार हो जाता है। सोचना यह होगा कि शिक्षा संस्थान की प्रासंगिकता बढ़ाई जाए या एक इमारत मान कर पर्यटन गांव की बाउंड्री कृषि विश्वविद्यालय में लगाई जाए। सरकार के राजनीतिक सलाहकारों और खास तौर पर कांगड़ा की ओर से सलाहकारों को अगर टूरिज्म कैपिटल के जुनून में केवल अपनी डफली बजानी है, तो भी इतना सुरूर ठीक नहीं कि बहते दरियाओं को रेगिस्तान बना दिया जाए।

एक ओर जमीन के लिए दर-दर की ठोकरें खाता पर्यटन गांव अब कृषि विश्वविद्यालय से भिक्षा मांग रहा है, जबकि दूसरी ओर तमाम स्वीकृतियों और बजट की अनुमतियों के बावजूद केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल परिसर पर सरकार की नीयत पर लोगों को शक होने लगा है। लगभग एक साल से सरकार को तीस करोड़ जमा करवा कर इस भूखंड पर विश्वविद्यालय की नींव को आश्वस्त करना है,

लेकिन कांगड़ा के सलाहकारों के लिए ऐसी पैरवी के लिए दो शब्द भी उपलब्ध नहीं हुए। इस दौरान अतिक्रमणकारियों के पांव तले जमीन का किसी को अंदाजा नहीं। योजनाएं-परियोजनाएं केवल वोट के ग्राहक ढूंढती रहीं और शहर ने खुद को खो दिया। ऐसा नहीं है कि पालमपुर में पर्यटक गांव को जमीन ही नहीं मिलेगी, लेकिन हमने विकास का आंगन जंगल को दे दिया। जंगलों के प्रदेश में जमीन पर डाका ऐसा कि हर कदम को ठोकर लगती है। उसके ऊपर भी तुर्रा यह कि जहां जंगल में हमने अपना प्राकृतिक रिश्ता खो दिया, वहां प्रदेश के 70 फीसदी हिस्से पर हमारा अपना कोई नियंत्रण और निमंत्रण नहीं। हमने राजस्थान की प्यास बुझाने के लिए पूरी हलदूण घाटी डुबो दी, लेकिन बदले में मिले अन्याय के दंश झेल रहे हैं। बांध के बाद पिछली बरसात में परियोजना ने बिना बताए गेट खोलकर जिन इलाकों की खेती और जीने के सुकून को छीन लिया, वहां अब फिर एक नई शिनाख्त शुरू हो गई। पौंग के किनारे बसे गांवों को ईको सेंसेटिव क्षेत्र घोषित करने की मुनादी का असर यह है घर का चूल्हा और गांव का बेहड़ा अपनी मौलिकता में जीने की हवा खोने लगा है।

हिमाचल की अपनी जरूरतें, तरक्की और आत्मनिर्भरता के रास्ते, विकास और अर्थव्यवस्था के तमाम विकल्पों पर हमारी ही जमीन हमारी दुश्मन बन बैठी है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, चंबा व सिरमौर के कई ऐसे इलाके भी वन भूमि में आ चुके हैं, जहां भविष्य का हिमाचल सांसें ले सकता है। मैदानी क्षेत्रों की वनों के तहत आई जमीन की वापसी के लिए संघर्ष नहीं होता है, तो आगे बढऩे के तमाम रास्ते केवल सियासी चुगलबाजी ही करेंगे। आज पर्यटन गांव के लिए कृषि विश्वविद्यालय से खेत छीन कर जमीन की आपूर्ति कर भी लें, तो कल अन्य परियोजनाओं के लिए क्या करेंगे। प्रदेश की आर्थिकी और नागरिक जरूरतों के हिसाब से नई बस्तियों, बाजारों, खेल-व्यापारिक मैदानों, उद्योग क्षेत्रों, मनोरंजन पार्कों, कनेक्टिविटी और नए शहरों के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है, वह केवल जंगल में उपलब्ध है। प्रदेश में अगर जंगल और सामान्य एवं सार्वजनिक भूमि की दर पचास-पचास प्रतिशत की सीमा तक कर दी जाए, तो भी अतिरिक्त जमीन से यह प्रदेश आत्मनिर्भरता के कदम उठा सकता है, वरना विकास का हर इश्तिहार केवल राजनीति ही करेगा।

राइडर्स के लिए इंश्योरेंस ऑप्शन लाने पर विचार कर रहा है इनड्राइव, इन शहरों में एक्टिव है सेवा

कंपनी के एक प्रतिनिधि ने शनिवार को कहा कि टैक्सी ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म इनड्राइव यात्रा के दौरान यात्रियों का बीमा करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी कंपनी इनड्राइव को 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था और अब यह कोलकाता दिल्ली मुंबई और कई अन्य शहरों जैसे प्रमुख महानगरीय शहरों में काम करती है। अधिकारी ने कहा कि वह अगले साल बेंगलुरु में सेवाएं देना शुरू कर देगी।

नई दिल्ली। inDRIVE कंपनी के एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म इनड्राइव यात्रियों को सवारी के दौरान बीमा प्रदान करने की योजना बना रहा है। भारत में 2019 में लॉन्च किया गया, यूएस-आधारित इनड्राइव अब कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और कुछ अन्य शहरों जैसे प्रमुख महानगरों में संचालित होता है। अधिकारी ने कहा कि यह अगले साल बेंगलुरु में सेवाएं शुरू करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि हम इनड्राइव सेवा का लाभ उठाने वालों को यात्रा के दौरान बीमा देने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल यह अभी योजना स्तर में है। यह भी दावा किया गया है कि यह ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म ₹कोलकाता में प्रतिदिन 10,000 ड्राइवर भागीदारों के साथ 30,000 सवारी पंजीकृत करता है।

सुरक्षा फीचर किया लॉन्च

अधिकारी ने कहा कि इनड्राइव जल्द ही अपने ऐप में एक सुरक्षा फीचर लॉन्च करेगा, जो सवारियों के फोन नंबर ड्राइवरों के साथ साझा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VOIP) पेश करेंगे ताकि सवार का फोन नंबर ड्राइवर को न दिखे। वीओआईपी कॉल सुरक्षित होंगी। अधिकारी ने कहा कि इनड्राइव ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों के साथ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है।

2023 में FPI ने किया 1.71 लाख करोड़ रुपये का भारी निवेश, यहां जानें सारी डिटेल

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है कि दिसंबर में प्रवाह में वृद्धि के कारण 2023 में एफपीआई द्वारा बड़ा निवेश हुआ है। एफपीआई प्रवाह जो पिछले तीन महीनों से नकारात्मक था दिसंबर में 66134 करोड़ रुपये की कुल खरीद के साथ काफी सकारात्मक हो गया। उन्होंने कहा कि 2023 में कुल एफपीआई प्रवाह 171106 करोड़ रुपये होगा।

नई दिल्ली। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है कि दिसंबर में प्रवाह में तेज बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2023 में एफपीआई द्वारा भारी निवेश देखा गया है। एफपीआई प्रवाह जो पिछले 3 महीनों में नकारात्मक था, दिसंबर में 66134 करोड़ रुपये की कुल खरीद के साथ तेजी से सकारात्मक हो गया है।

बता दें कि इस आंकड़े में स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खरीदारी और प्राथमिक बाजार में निवेश शामिल है। उन्होंने कहा कि 2023 में कुल एफपीआई प्रवाह 171106 करोड़ रुपये है।

लगातार गिरावट के कारण रणनीति में बदलाव

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में लगातार गिरावट के कारण एफपीआई की रणनीति में यह अचानक बदलाव आया है। दिसंबर में, एफपीआई वित्तीय सेवाओं में बड़े खरीदार थे,जो दिसंबर में इस खंड के लचीलेपन को बताता है।

एफपीआई ने ऑटो, पूंजीगत सामान और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी खरीदारी की।

उन्होंने कहा, चूंकि 2024 में अमेरिकी ब्याज दरों में और गिरावट देखने की उम्मीद है, इसलिए एफपीआई द्वारा 2024 में भी अपनी खरीदारी बढ़ाने की संभावना है, खासकर आम चुनावों से पहले 2024 के शुरुआती महीनों में आपको यह बदलाव देखने को मिल सकता है।

नए साल में कम हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए आपके शहर में क्या है कीमत

रोज की तरह आज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को रिवाइज कर दिया गया है। महानगरों के साथ साथ देश के सभी छोटे बजे शहरों के आज के नए दाम सामने आ गए है। बता दें कि नए साल में इसकी कीमत में कमी आने की बात सामने आई है। आइये जानें आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल-डीजल की कीमत कितनी है

नई दिल्ली। नए साल के आगाज के साथ ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आने की आशंका जताई जा रही है। मई 2022 के बाद से कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलता है।

बता दें कि पेट्रोल-डीजल की कीमत पर सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमतों के कारण पड़ता है। इसके अलावा देश की सरकारी तेल कंपनियों यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनकी कीमतों पर टैक्स, वैट, कमीशन आदि लगाते हैं।

रोज सुबह 6 बजे इसकी कीमतों को अपडेट किया जाता है आइये जानते हैं, आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल-डीजल की कीमत क्या है।

महानगरों में ये रही कीमतें

पेट्रोल-डीजल की कीमतें महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-में स्थिर ही है।

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की दरें क्रमशः 96.72 रुपये और 89.62 रुपये प्रति लीटर हैं।

मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.77 रुपये और डीजल की कीमत 94.27 रुपये है।वहीं कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल 106.03 रुपये का और डीजल 92.76 रुपये पर मिल रहा है।

अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल के कीमत

नोएडा में पेट्रोल 96.59 रुपये और डीजल 89.76 रुपये हो गया है।

गुरुग्राम में पेट्रोल 96.84 रुपये और डीजल 89.72 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

हैदराबादः पेट्रोल 109.66 रुपये और डीजल 97.82 रुपये प्रति लीटर

चंडीगढ़ः पेट्रोल 96.20 रुपये और डीजल 84.26 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरुः पेट्रोल 101.94 रुपये और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर

लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

जयपुर में पेट्रोल 108.48 रुपये और डीजल 93.72 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

भुवनेश्वर में पेट्रोल 103.19 रुपये और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

620.44 अरब डॉलर पहुंचा कुल विदेशी मुद्रा भंडार, लगातार तीसरे सप्ताह जारी रही वृद्धि

परिवहन विशेष न्यूज

बीते सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 4.47 अरब डालर की वृद्धि हुई है। आरबीआई की ओर से शुक्रवार को जारी डाटा के अनुसार में पता चला है कि देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 620.44 अरब डालर पर पहुंच गया है। यह इसका 21 महीने का उच्च स्तर है। डाटा के अनुसार बीते 3 सप्ताहों से विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह वृद्धि जारी रही। 22 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में इसमें 4.471 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे कुल मुद्रा भंडार 620.441 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, किटी 9.112 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 615.971 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई थी, जिससे वृद्धि की मात्रा एक सप्ताह में सबसे अधिक हो गई। इससे पहले सप्ताह में, कुल भंडार 2.816 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 606.859 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था।

अक्टूबर 2021 में, विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। जो इस हफ्ते के 620 बिलियन अमेरिकी डॉलर से केवल 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर दूर है। पिछले साल से वैश्विक विकास के कारण दबाव के बीच केंद्रीय बैंक ने रुपये की रक्षा के लिए पूंजी भंडार को तैनात कर दिया, जिससे भंडार प्रभावित हुआ।

इस साल हुई 57.634 बिलियन डॉलर बढ़ोतरी

केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 57.634 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। रिज़र्व बैंक डाटा के अनुसार, 22 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में 4.69 अरब डालर की वृद्धि हुई है। अब कुल एफसीए बढ़कर 549.747 अरब डालर हो गया है।

हालांकि, इस दौरान स्वर्ण भंडार में करीब 10.7 करोड़ डालर की कमी रही है और यह घटकर 47.47 अरब डालर हो गया है। डाटा के अनुसार, पूरे 2023 के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 57.634 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

नए साल के आगाज के साथ ही बदल जाएंगे ये नियम, जान लें नहीं तो हो सकती है परेशानी

New Rules in 2024 2024 की शुरुआत के साथ ही कुछ ऐसे नियम होंगे जिसमें आपको बदलाव दिखाई देगा। ये बदलाव आधार कार्ड से लेकर सिम कार्ड तक हो सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नए साल के शुरुआत के साथ ही कौन-कौन से ऐसे नियम है जो बदल जाएंगे और इनका आम जनता पर क्या प्रभाव पडेग़ा। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। नए साल में केवल 2 दिन बाकी है और इसके आने के साथ बहुत से ऐसे नियम हैं, जो बदल जाएंगे। ये नियम इतने प्रभावी हैं कि हर किसी को इसका असर दिखाई दे सकता है। बता दें कि इस साल सरकार आधार, UPI अकाउंट को डिएक्टिवेट करना, सिम कार्ड की पेपरलेस केवाईसी से जुड़े कुछ बदलाव होंगे।

वैसे हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियम लागू होते हैं। इनका सीधा असर आम आदमी के डेली लाइफ पर पड़ता है, इसलिए जरुरी है कि आप इसके बारे में विस्तार से जानें और 31 दिसंबर को इन बदलावों को करा लें।

सिम कार्ड की पेपरलेस KYC

नए साल के आने के साथ सिम कार्ड को लेकर कई जरूरी घोषणाएं की जाएगी। 1 जनवरी नई सिम खरीदते वक्त आपको पेपर-बेस्ट नो योर कस्टमर (KYC) की जगह पेपरलेस केवाईसी ले लेगी। इस प्रक्रिया के साथ आपको बायोमेट्रिक के जरिए अपनी डिटेल्स की पुष्टि करनी होगी।

बदलेंगे ITR फाइल करने के नियम

बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। ऐसे में अगर आप समय रहते ITR फाइल करने है तो आपको खिलाफ एक्शन लेगा।

बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन 31 दिसंबर 2023 विलंबित और संशोधित ITR भरने की आखिरी तारीख है।

देर से आईटीआर फाइल करने पर आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बंद होंगे इनएक्टिव UPI अकाउंट

UPI अकाउंट को लेकर भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन (NPCI) ने पेमेंट ऐप्स को उन UPI आईडी को डिएक्टिवेट करने का आदेश दिया है।

NPCI ने कहा कि जो 31 दिसंबर तक जो भी अकाउंट एक साल से अधिक समय से इनएक्टिव हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए।

आधार अपडेट के नियम

जैसा कि हम जानते हैं सरकार लंबे समय से लोगों को अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कह रही है। मगर अब इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।

ऐसे में अगर आप इस तारीख के बाद अपडेट कराते हैं तो आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

बैंक लॉकर से जुड़े नियम

RBI ने बैंक लॉकर धारकों को 31 दिसंबर तक संशोधित बैंक लॉकर अग्रीमेंट पर साइन करने को कहा है, क्योंकि अगले दिन से आपके लॉकर फ्रीज कर दिए जाएंगे।

डीमैट अकाउंट से जुड़े नियम

बता दें कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो सेबी ने कहा है कि डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की बात पर जोर दिया था। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।

अगर आप अकाउंट होल्डर्स में नॉमिनी नहीं जोड़ेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट 1 जनवरी 2024 से फ्रीज हो सकता है।

2024 में 14 दिन बंद रहेगा बाजार, यहां देखें नए साल में शेयर मार्केट की छुट्टियों की लिस्ट

Stock Market Holiday आने वाले साल में शेयर मार्केट 15 दिनों तक बंद रहेगा। NSE और BSE ने इसकी जानकारी दी है कि 2024 में कुछ 14 दिनों का ट्रेडिंग हॉलीडे होगा। इस साल में आपको लगभग चार एक्सटेंडेड हॉली डे मिलेंगे। इसके अलावा 5 ऐसी छुट्टियां भी है जो शनिवार और रविवार को होगी जिसमें दिवाली और दशहरा शामिल है।

नई दिल्ली। साल खत्म होने में केवल दो दिन बाकी है। ऐसे में नए साल के बहुत कुछ बदल जाएगा और शेयर मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इस साल शेयर बजार कुल 14 दिनो तक बंद रहेगा। NSE और BSE ने इसकी जानकारी दी है।

इसके अलावा ये भी पता चला है कि अगले साल की चार छुट्टियों ऐसी है, जिसके साथ आपको एक्सटेंडेड हॉली डे का लाभ मिलेगा, यानी ये छुट्टियां शुक्रवार या सोमवार को होती है। आइये इस साल की छुट्टियों के बारे में जानते हैं।

मिलेगी एक्सटेंडेड छुट्टियां

BSE की लिस्ट छुट्टियों में चार छुट्टिया ऐसी है, जो एक्सटेंडेड वीकेंड के साथ आएंगी। साल का पहला महीना ही ऐसी एक छुट्टी के साथ आएगा। 26 जनवरी (शुक्रवार) को शेयर बाजार बंद रहेगा, जिस कारण लगातार 3 दिन मार्केट ओपन नहीं होगा।

इसके बाद मार्च में तीन ऐसी छुट्टिया होगी, जिसमें 8 मार्च (शुक्रवार) को महाशिवरात्रि, 25 मार्च (सोमवार) को होली और 29 मार्च को गुड फ्राइडे शामिल हैं। 17 जून (सोमवार) को बकरीद के अवसर पर बाजार बंद रहेगा।

इन महीनों में दो दिन बंद रहेगा बाजार

लिस्ट में ये भी पता चला है कि अप्रैल, जुलाई और नवंबर में दो दिन बाजार बंद रहेंगे। जहां अप्रैल में 11 अप्रैल (गुरुवार) को ईद-उल-फितर (रमजान ईद) और 17 अप्रैल (बुधवार) राम नवमी पड़ेगी।

वहीं 17 जुलाई को मुहर्रम मनाया जाएगा और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को मार्केट बंद रहेगा। अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती (2 अक्टूबर) बुधवार को भी मार्केट बंद रहेगा।

नबंबर में भी है लंबी छुट्टियां

दिवाली के अवसर 1 नवंबर को मार्केट बंद रहेगा। हालांकि इस दिन एक विशेष मुहूर्त कारोबार होगा, जिसके समय की घोषणा उसी समय की जाएगी।

वहीं 15 नवंबर को गुरुनानक जयंती शुक्रवार को मनाई जाएगी, जिसके कारण लंबी छुट्टी भी रहेगी। इसके अलावा 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के लिए बाजार बंद रहेगा।

कमोडिटी बाजार में छुट्टियां

कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार के लिए पांच ट्रेडिंग छुट्टियां मिलेगी और मार्केट पूरे दिन के लिए बंद रहेगा, जिसमें गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और क्रिसमस शामिल है।

इसके अलावा बाकी छुट्टियों में कमोडिटी बाजार शाम के सत्र के लिए खुलेगा। वहीं कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार नए साल यानी 1 जनवरी को शाम के सत्र के लिए बंद रहेगा।

कोहरे का कहर: दिल्ली एयरपोर्ट पर 80 उड़ानों में देरी, कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से हुईं लेट; यात्री परेशान

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक कोहरा छाया हुआ है। मौसम की स्थिति के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग 80 उड़ानों में देरी की सूचना है।

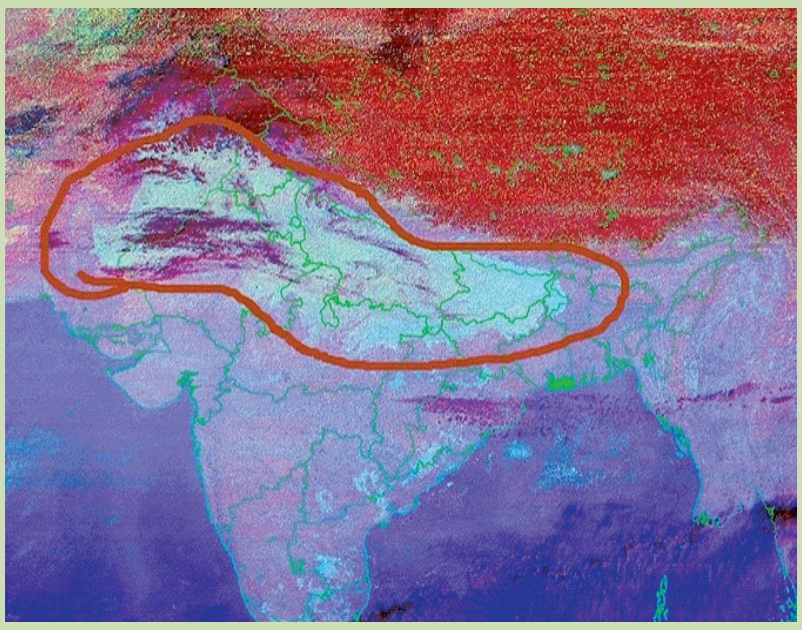

दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि आज सुबह 8.30 बजे तक आईजीआई एयरपोर्ट से जाने वाली करीब 80 फ्लाइट लेट हैं। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम की वजह से उड़ान सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। इसकी वजह से कई फ्लाइट निर्धारित समय से काफी लेट हैं

दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह 8:30 बजे तक आईजीआई एयरपोर्ट से जाने वाली करीब 80 फ्लाइट लेट हैं। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम की वजह से उड़ान सेवाओं पर भारी असर पड़ रहा है। इसकी वजह से कई फ्लाइट निर्धारित समय से काफी लेट हैं। वहीं, कई ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। जानकारी के अनुसार, तेलंगाना एक्सप्रेस 3.40 घंटे, पंजाब मेल 6.07, गोरखधाम एक्सप्रेस, श्रमशक्ति एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, दादर एक्सप्रेस, बांद्रा-श्रीमात वैष्णो देवी समेत कई ट्रेनें शामिल हैं।

जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर-25, पंजाब में अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला-25 प्रत्येक, हरियाणा में अंबाला-25, करनाल, हिसार-50, दिल्ली के आयानगर, सफदरजंग-200, पालम, दिल्ली-रिज-500, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के झांसी, मेरठ-50, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर-200, लखनऊ, वाराणसी, सुल्तानपुर-500, पूर्वी मध्य प्रदेश के सतना-25, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह-50, गुना-200, ग्वालियर, भोपाल-500, झारखंड के डाल्टनगंज-200 मीटर कोहरा दर्ज किया गया।

नए साल के जश्न में बरतें सावधानी, बढ़ सकता है कोरोना

नई दिल्ली। धीमी गति से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच विशेषज्ञों ने नए साल के जश्न में सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में फ्लू के मामले बढ़ते हैं। मौजूदा समय में अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। अनुमान है कि हर परिवार में कोई न कोई खांसी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण से परेशान है। यदि इस दौरान नए साल के जश्न के दौरान लापरवाही बढ़ती है तो कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसा होने पर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज, बुजुर्ग और बच्चों की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए, साथ ही मास्क का प्रयोग करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कोरोना के 45 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में जेएन.1 वैरिएंट का एक मामला सामने आया है।

सफदरजंग अस्पताल में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के निदेशक, प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. जुगल किशोर का कहना है कि जेएन.1 ओमिक्रॉन का एक उप-संस्करण है। फिलहाल इसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना चाहिए। लोकनायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. सुरेश कुमार का कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। यदि किसी व्यक्ति में कोई लक्षण है तो जांच करवानी चाहिए।

ज्यादातर मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव

अस्पताल में कोरोना के लक्षणों के साथ पहुंच रहे ज्यादातर मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में वैसे भी फ्लू काफी सक्रिय रहा है। यह कोरोना की तरह ही परेशान करता है।

ईडी ने संजय भंडारी की संपत्ति को जब्त करने के लिए दिया आवेदन, ब्रिटेन में है प्रॉपर्टी

ईडी ने कथित रक्षा डीलर संजय भंडारी की ब्रिटेन में दो संपत्तियों को जब्त करने के लिए अदालत दिया है। ग्रोसवर्नर हिल कोर्ट में दो अचल संपत्तियों को अपराध की आय और भंडारी की अघोषित विदेशी संपति बताया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित रक्षा डीलर संजय भंडारी की यूनाइटेड किंगडम में दो संपत्तियों को जब्त करने के लिए यहां एक अदालत का रुख किया है। इसमें एक कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा द्वारा पुनर्निर्मित और रुकी हुई संपत्ति भी शामिल है। एजेंसी ने लंदन में 15 बॉर्डन स्ट्रीट पर 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर और 6, ग्रोसवर्नर हिल कोर्ट में स्थित दो अचल संपत्तियों को अपराध की आय और भंडारी की अघोषित विदेशी संपत्ति बताया है।

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा ने पहले इस बात से इनकार कर चुके हैं कि उनके पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लंदन की कोई संपत्ति है। ईडी ने पिछले महीने इस मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल करते हुए विशेष अदालत से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दो संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगी थी। अभियोजन की शिकायत 22 दिसंबर को रिकॉर्ड पर ली गई और मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

ईडी की मंगलवार को जारी बयान में कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने सुमित चड्ढा के माध्यम से न केवल लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में उक्त संपत्ति का नवीनीकरण किया, बल्कि उसी में रहे भी। ईडी और सीबीआई भंडारी के खिलाफ विदेश में घोषित रखने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कर चोरी की जांच कर रही हैं। भंडारी की इन संपत्तियों में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर की संपत्ति भी शामिल है।

एलजी का आदेश :- अब दिल्ली वाले घर बैठे कर सकेंगे भ्रष्टाचार की शिकायत, जानें कैसे ?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण एवं छापेमारी करने के निर्देश दिए. तकनीकी के इस दौर में घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक से सारी सुविधाएं उपलब्ध है. ऐसे में लोगों की समस्याओं के निवारण और शिकायतों के लिए भी अब पोर्टल और एप्स शुरू किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अब दिल्लीवासियों को आने वाले समय के भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पडेगी. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा आयोजित की गई बैठक में अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आम जन घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अब भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे.

शिकायत के साथ भेज सकेंगे फोटो/विडियो

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और विभिन्न विभागों के मुख्त सतर्कता अधिकारियों के साथ बैठक की. जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके निर्देश पर देश में पहली बार भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट इंफोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (ओ सी आई एम एस) तैयार किया जा रहा है. एनआईसी द्वारा तैयार किए जा रहे इस पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के साथ फोटो, वीडियो और ऑडियो भी भेज सकेंगे.

बैठक में उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण एवं छापेमारी करने के निर्देश दिए. एलजी के इस आदेश के बाद से दिल्ली के अलग-अलग विभागों में कार्यरत अधिकारी सकते में हैं. ऐसा इसलिए कि अब लोग अपनी शिकायत सीधे एलजी तक पहुंचा पाएंगे.

साक्ष्य के साथ ई-एफिडेविट देना अनिवार्य

उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह इस पोर्टल पर शिकायत का संतुलन बनाने के बंदोबस्त करें. एक तरफ जहां भ्रष्टाचार करने वालों को सजा मिले तो वहीं दूसरी तरफ झूठी शिकायतों से किसी अधिकारियों को नाहक परेशानी न झेलनी पड़े. इसके लिए उन्होंने शिकायत के साथ साक्ष्य अपलोड को अनिवार्य करने की सलाह दी है. इसके अलावा शिकायतकर्ता को अपना आधार नंबर और दी गई जानकारी की सत्यता से संबंधित एक ई-एफिडेविट भी देना होगा।

प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक जारी है. आगामी चुनाव के लिए रणनीति की तैयारी

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबानेश्वर : प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है. जिला अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ बैठक चल रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख बी.एल. सत्या, क्षेत्र प्रभारी सुनील बंसल , सह प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं. आधिकारिक बैठक में होने वाले निर्णय को जमीन पर उतारने का निर्णय लिया जायेगा. हर बूथ से 50 फीसदी से ज्यादा वोट पाने का ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है. इसी तरह संयुक्त मोर्चा की बैठक कल होगी. कहा जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के बाद ओडिशा में भी यही फॉर्मूला अपनाएगी. चर्चा है कि जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो सकती है।

जेएनएनवाईसी का एक हिस्सा सील, युवा केंद्र ने बताया कार्रवाई को अवैध

प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, 99 साल के पट्टे पर चल रहा डीडीयू मार्ग पर ट्रस्ट का दफ्तर, विधिक व्यक्ति के कहने पर ही शाश्वत डीड रद्द हो सकती है। जेएनएनवाईसी पदाधिकारी बोले, उसी शख्स के कहने पर केंद्र सरकार के भूमि व विकास कार्यालय ने की कार्रवाई, जिसको तीन साल पहले हटाने का निर्देश दिया था।

राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र (जेएनएनवाईसी) के एक हिस्से को शनिवार सुबह केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने बंद कर दिया है। अपनी कार्रवाई के हक में अधिकारियों ने जेएनएनवाईसी की बैठक में पारित एक प्रस्ताव का हवाला दिया है। इस पर सख्त एतराज जताते हुए जेएनएनवाईसी पदाधिकारियों का कहना है कि एलएंडडीओ ने जिस शख्स पुरुषोत्तम गोयल की तरफ से बुलाई गई बैठक में पारित प्रस्ताव पर कार्रवाई की, उसे ट्रस्ट से निकालने का आदेश तीन साल पहले खुद एलएंडडीओ ने ही दे रखा है। वहीं, हाई कोर्ट ने भी 20 जुलाई 2015 में इस पर प्रोविजनल स्टे है। इसके बावजूद एलएंडडीओ का दस्ता कार्रवाई करने पहुंचा है। ऐसे में यह कार्रवाई पूरी तरह अवैध है। ट्रस्ट का दफ्तर 99 साल की शाश्वत डीड पर डीडीयू मार्ग पर चल रहा है। डीड में बदलाव विधिक व्यक्ति की स्वीकृति के बाद ही दिया जा सकता है। अधिकारियों ने शनिवार की कार्रवाई के खिलाफ अदालत में जाने की बात कही है।

जेएनएनवाईसी दफ्तर 1972 में 99 साल की लीज पर मिला

जेएनएनवाईसी के प्रशासनिक अधिकारी व दिल्ली इकाई के प्रमुख पंकज पांडेय का कहना है कि दीन दयाल मार्ग स्थित जेएनएनवाईसी दफ्तर 1972 में 99 साल की लीज पर मिला था। प्रवीण सिंह ऐरन 1988 से महासचिव हैं। 2014 में इनको महानिदेशक भी बना दिया गया। ट्रस्ट इनके अधीन ही संचालित होता है। इस पर इस वक्त विधिक अधिकार इनका ही है। आरोप है कि 2018 से पुरुषोत्तम गोयल नामक एक व्यक्ति ने खुद को महासचिव बताकर लगातार दावेदारी की है। अक्तूबर 2020 में भूमि व विकास कार्यालय ने गोयल का अवैध व्यक्ति बताकर इनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था।

पुरी में 5T चेयरमैन भी के पांडियन के खिलाफ काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन

मनोरंजन सासमल ओड़िशा

भुबनेश्वर: 5T के अध्यक्ष भी के पंडियन को पुरी में काला झंडा दिखाकर के विरोध प्रदर्शन. आज सुबह 5 बजे जब भी के पांडियन पुरी आये तो जिला कांग्रेस ने उनका विरोध किया। कांग्रेसियों ने काला झंडा दिखाया और ₹पांडियन गो बैकर₹ के नारे लगाए। श्रीमंदिर के प्रशासनिक कार्यालय में 10 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पांडियन को काले झंडे दिखाए.पुलिस ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है. समूह ने सौंदर्यीकरण के नाम पर मठों और मंदिरों को मिट्टी में मिलाने, यूट्यूब के काम्या जानी विवाद और दुनिया में जगन्नाथ संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, कांग्रेस के विरोध को लेकर बिजेड़ी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हाल ही में भद्रक रोड स्थित बाबा अखंडलमणि मंदिर में आम ओडिशा नवीन ओडिशा के चेयरमैन भी.के. पांडियन का विरोध किया गया । पांडियन दर्शन समाप्त होने के बाद, मंदिर के सेवकों ने गोबर जल और गंगा जल छिड़का। सेवायत ने आरोप लगाया कि गाय का मांस खाने वाले कामिया जानी का पांडियन जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश भारतीय संस्कृति की परंपराओं को नष्ट कर रहा है। हालांकि, बिजेड़ी की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई ।

अखिल भारतीय सीरवी समाज खेल प्रतियोगिता राजस्थान जिला ब्यावर तहसील रायपुर में आयोजित

परिवहन विशेष न्यूज

अखिल भारतीय सीरवी समाज खेल प्रतियोगिता राजस्थान जिला ब्यावर तहसील रायपुर जगदीश सीरवी 29 दिसम्बर महाकुंभ 2023 के महापर्व मैं भाग लेने वाले सभी टीमों के कप्तान और खिलाड़ियों , प्रतियोगिता आयोजन करने वाले अखिल भारतीय सीरवी महासभा के तत्वाधान में सीरवी समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, कुशालपुरा द्वारा आयोजित चतुर्थ अखिल भारतीय सीरवी समाज खेल प्रतियोगिता के समस्त भामाशाहों , अखिल भारतीय सिरवी समाज खेल परिवार के सदस्यों और प्रतियोगिता को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तन,मन, धन और दिल से सहयोग करने वाले सभी मान्यवरों और चेन्नई कर्नाटक तेलंगाना महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान खेल परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद सीरवी समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, कुशालपुरा के सभी मान्यवर सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूं आपने बहुत ही खूबसूरत मेनेजमेंट, मेहमान नवाजी ,सुपर खाना पीना और इतना बड़ा ग्राउंड और उतनी ही अच्छी लाईव कवरेज बहुत बहुत धन्यवाद करता हूंहमने ग्राउंड और टीवी पर लाइव मैचों को देखा मजा आ गया। इतना बड़ा आयोजन करना बहुत मेहनत ,लगन, संगठित, धैर्यवान और सहनशील होना पड़ता है तभी जाकर काम सफल होते हैं और वो के कुशालपुरा मान्यवरों ने वो करके दिखाया मैं अध्यक्ष और उनकी पुरी टीम को धन्यवाद करता हूं बड़े शान्त रहकर आपने धैर्य का परिचय दिया। एक बार फिर आखिल भारतीय सिरवी समाज खेल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद सामहाकुंभ 2023 की विजेता और उपविजेता टीम को बहुत बहुत बधाई देता हु

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023